04 - असुरक्षा का भाव चमका रहा है बाबाओं का धंधा

05 - सहिष्णु समाज में पहचान की राजनीति के मायने

06- 198.02 करोड़ की 11 सिंचाई परियोजनाओं की मंजूरी

07- खारे पानी की समस्या से जूझते ग्रामीण इलाके

A Daily News Magazine

इंदौर

बुधवार, 24 जुलाई, 2024

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 9 अंक 273, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2 (डाक पंजीयन संख्याः MP/IDC/1529/2016-2018)

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

बजट 2024 : बिहार-आंध्र पर फोकस के पीछे क्या कहानी कुछ और है..?

शादाब मोइज़ी

'जिनके समर्थन से चल रही है मोदी सरकार, उनके लिए खुले भंडार'.. ये लाइन मोदी सरकार 3.0 सॉरी एनडीए सरकार 3.0 के पहले बजट का लब्बोलुआब यानी सार, निचोड़ है। दरअसल, लोकसभा स्पीकर के चुनाव से लेकर मंत्रालय के बंटवारे में जहां बीजेपी हावी दिख रही थी, वहीं बजट 2024 में नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के प्रेशर पॉलिटिक्स की झलक देखने को मिली।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट 2024 संसद में पेश कर दिया है। बजट में सीतारमण ने बिहार को करीब 59 हजार करोड़ रूपये के प्रोजेक्ट की घोषणा की है। जिसमें से 26000 करोड़ रुपये बिहार में एक्सप्रेस-वे और सड़क बनाने के लिए दिए जाएंगे। वहीं आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की है।

इस आर्टिकल में आपको आगे बताएंगे कि बजट 2024 में बिहार और आंध्र प्रदेश को क्या खास मिला है और क्या सिर्फ नीतीश और नायडू को खुश करना मकसद है या बीजेपी का कुछ और गेम प्लान है?

इस गेम प्लान, प्रेशर पॉलिटिक्स और बजट के बड़े ऐलान के मायने समझने से पहले राजनीति का नंबर गेम देख लीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया लेकिन 240 सीटों पर सिमट गई। मतलब बहुमत के लिए 272 सीटों से बीजेपी 32 सीट पीछे रह गई। वहीं चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को 16 और नीतीश कुमार की जदयू को 12 सीटों पर जीत मिली। यानी कि सरकार बनाने के लिए इन दोनों का साथ अहम था।

'बड़े' ऐलान के पीछे क्या वजह?- हार और आंध्र प्रदेश के स्पेशल कैटेगरी की मांग नीतीश से लेकर चंद्रबाबू नायडू करते रहे हैं, लेकिन बजट से ठीक एक दिन पहले संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा था कि अंतर-मंत्रालयी समूह (IMG) की 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार को विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता।

इस जवाब के बाद विपक्षी दलों ने बीजेपी पर हमला तेज कर दिया, हालांकि बीजेपी की साथी पार्टियों ने इंतजार करने का रास्ता चुना। शायद उन्हें पता होगा कि स्पेशल स्टेटस की जगह 'स्पेशल पैकेज' मिलेगा।

लेकिन सवाल है कि क्या ये सिर्फ नीतीश और नायडू का प्रेशर है या कहानी कुछ और है? थोड़ा इन घोषणाओं पर नजर डालेंगे तो समझ आएगा कि सब प्रेशर पॉलिटिक्स ही नहीं बल्कि बीजेपी का अपना फायदा भी है।

भाजपा की नजर बिहार पर..- बीजेपी बिहार में आजतक अपने बल पर सरकार नहीं बना सकी है। करीब पिछले दो दशक से बीजेपी, नीतीश कुमार के सहारे बिहार में सत्ता में है। लेकिन ये भी सच है कि विधानसभा में नीतीश कुमार कमजोर होते गए और बीजेपी मजबूत।

इसे आप ऐसे समझिए कि जब 2015 में आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था तब आरजेडी 80, जेडीयू 71 और बीजेपी को सिर्फ 53 सीट हासिल हुई थी। फिर 2020 के चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर लड़ने के बावजूद जेडीयू 71 से घटकर 43 सीटों पर आ गई यानी पार्टी को 28 सीटों का नुकसान हुआ था। जबकि बीजेपी 21 सीटों की बढ़त के साथ 53 से 74 पर पहुंच गई।

इसका मतलब साफ है कि बीजेपी बिहार में आने वाले वक्त में एकला चलो की राह पर सरकार बनाना चाहेगी। अब ऐसे में नीतीश कुमार के स्पेशल स्टेटस की मांग मानकर वो खुद को प्रेशर में दिखाना नहीं चाहेगी। और अगर स्पेशल स्टेटस दे दिया तो फिर नीतीश क्रेडिट ले जाएंगे, जिसका जोखिम बीजेपी उठा नहीं सकती है।

जानकार मानते हैं कि यही वजह है कि बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार को स्पेशल स्टेटस की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों के लिए करोड़ों रुपए के स्पेशल पैकेज देकर क्रेडिट और मैसेजिंग की लड़ाई में आगे दिखना चाहती है।

बिहार को क्या मिला?- वित्त मंत्री ने बजट भाषण में ईस्टर्न रीजन के चहुंमुखी विकास के लिए पूर्वोदय योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश आएंगे। आइए जानते हैं बिहार को क्या खास मिला?

- बिहार में कई सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।
- पटना-पूर्णिया, बक्सर-भागलपुर, और बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा को जोड़ने के लिए एक्सप्रेस-वे बनाने की घोषणा की गई।
- बिहार के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा।
- बिहार में सिंचाई और बाढ़ से निपटने और राहत के लिए 11,500 करोड़ रुपए देगी।
- नए मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे।
- स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जाएगा।
- महाबोधि मंदिर और विष्णुपद मंदिर को विकसित किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश को क्या मिला?- निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का ऐलान किया है। जो राज्य की राजधानी और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के ड्रीम प्रोजेक्ट अमरावती को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि विशाखापत्तनम-चेन्नई-ओरवाकल-हैदराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा, साथ ही एक हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा भी स्थापित किया जाएगा जो आंशिक रूप से आंध्र प्रदेश को कवर करेगा। रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी आंध्र प्रदेश जिलों के लिए एक स्पेशल बैकवार्ड एरिया फंड की भी घोषणा की गई है। आंध्र प्रदेश की पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। यह परियोजना आंध्र प्रदेश और इसके किसानों के लिए लाइफलाइन है।

खोला खजाना, सबका होगा 'मंगल'

- **3 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री, गरीबों, किसानों और महिलाओं के लिए खुला खजाना**
- **भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 9 प्राथमिकताओं पर सरकार का जोर**
- **नौकरी और कौशल विकास पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का वित्तमंत्री का ऐलान**
- **महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं पर 3 लाख करोड़ रुपए होंगे खर्च**

नई दिल्ली (एजेंसी)। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कमर कस ली है। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट भाषण पढ़ा तो यही बात नजर आई। निर्मला सीतारमण ने सातवीं बार बजट पेश किया है। यह मोदी सरकार का यह 13वां बजट है, जिसमें निर्मला ने कहा कि यह बजट गरीब, महिला, युवा और अन्नदाताओं पर फोकस है। भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में अपना विश्वास तीसरी बार जताया है। वहीं, मुश्किल दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से चल रही है। निर्मला के इस बजट में आम आदमी को थोड़ी सी राहत देते हुए नए टैक्स रिजीम में बदलाव किया गया है, जिसके तहत 3 लाख तक की इनकम अब टैक्स फ्री होगी। वहीं, पुरानी टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स से छूट पहले की ही तरह जारी रहेगी। यानी सरकार धीरे-धीरे नई टैक्स रिजीम की ओर बढ़ रही है। निर्मला के सभी प्रमुख ऐलान को समझते हैं।

क्या हुआ सस्ता, क्या महंगा

ये होंगे सस्ते	इनके बढ़ेंगे दाम
चमड़े के जूते	सिगरेट
कपड़े	हवाई जहाज से यात्रा
सोना-चांदी	प्लास्टिक का सामान
मोबाइल फोन	पेट्रोकेमिकल
मोबाइल चार्जर	इलेक्ट्रिक व्हीकल
कैंसर दवा	प्लेटिनम
बिजली के तार	एक्सरे मशीन
सोलर सेट्स	

पुरानी टैक्स रिजीम पर कोई राहत नहीं, नए में 75 हजार तक छूट

वित्त मंत्री ने नए टैक्स रिजीम के लिए डिडक्शन की लिमिट 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दी है। नए टैक्स रिजीम पर अब 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं, पुराने टैक्स रिजीम पर कोई राहत नहीं दी है। नए टैक्स रिजीम में तीन लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तीन से 7 लाख रुपये पर इसे 5 फीसदी कर दिया है। सात लाख से 10 लाख रुपए तक 10 फीसदी, 10 से 12 लाख तक 15 फीसदी और 12 से 15 लाख रुपए तक 20 फीसदी और 50 लाख तक 30 फीसदी टैक्स लगेगा।

पीएम गरीब कल्याण योजना 5 साल के लिए बढ़ी

निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा-प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है, जिसका लाभ देश के 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। हमारी सरकार का पूरा फोकस रोजगार, हुनर और युवाओं पर है। इस समय देश में मुद्रास्फीति फिलहाल 3.1 फीसदी पर है। इस साल 1.48 लाख करोड़ शिक्षा और रोजगार के लिए खर्च किए जाने का प्रस्ताव है।

एजुकेशन लोन 10 लाख तक, ब्याज पर भी छूट

वित्त मंत्री ने घरेलू संस्थानों में हायर एजुकेशन के लिए लोन 10 लाख तक किए जाने भी ऐलान किया। घरेलू संस्थानों में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3 फीसदी की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे।

नीतिश को 59 हजार करोड़, नायडू को 15 हजार करोड़ की सौगात

नई दिल्ली (एजेंसी)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार सातवीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतिश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान रही। नीतिश के बिहार को 59 हजार करोड़ और नायडू के आंध्रप्रदेश को 15 हजार करोड़ की सौगात मोदी सरकार ने बजट में दी है। बजट में नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। उन्हें सरकार अधिकतम 15 हजार रुपए तीन किश्तों में देगी।

मोबाइल फोन सस्ते होंगे, सोना-चांदी पर भी ड्यूटी घटाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। अब बजट में गिनी-चुनी चीजें ही सस्ती या महंगी होती हैं। सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देशभर में जीएसटी लागू किया था, जिसके बाद से बजट में केवल कस्टम और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई-घटाई जाती है। ड्यूटी के बढ़ने और घटने का का इनडायरेक्ट असर चीजों की कीमतों पर पड़ता है। तो इस बार सरकार ने मोटे तौर पर 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है और 2 की ड्यूटी बढ़ा दी है। बीते एक साल में सोना-चांदी 13,000 रुपए महंगे हुए है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 300 रुपए घटे हैं। इस दौरान तुअर दाल करीब 30 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है। सोयाबीन तेल, आटा और चावल के दामों में ज्यादा बदलाव नहीं आया है।

खेती-किसानी में डिजिटल ढांचे को मजबूती

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार की कृषि, रोजगार और सामाजिक न्याय प्राथमिकताएं हैं। हमारी प्राथमिकताओं में शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा भी शामिल है। कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और क्षमता प्राथमिकता बेहद जरूरी है। दलहन-तिलहन की उत्पादकता और भंडारण बढ़ाएंगे। 30 फसलों की 109 किस्में जल्द मिलेंगी। हमारा लक्ष्य तिलहन उत्पादों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। कृषि में डिजिटल ढांचे को मजबूती देंगे, ताकि उत्पादकता बढ़ सके। 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे होगा।

किसान सम्मान निधि नहीं बढ़ेगी, एमएसपी पर कोई ऐलान नहीं- वित्त मंत्री ने खेती और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। यानी इस बार किसानों के लिए बजट 25 हजार करोड़ रुपए बढ़ाया है।

सुप्रभात

तार पर झूलती हुई बूँदें
यह बताने के लिये ठहरी हैं
कि कल रात
कोई उतरा था जमीं पर,
प्यार का समन्दर लुटा कर
वह चला गया,
जब तुम गहरी नींद में थे।
कुछ बूँदें मिट्टी से गले मिलीं,
कुछ नदी में जा मिलीं,
कुछ तितलियों को चूमती हुई
पारिजात के फूलों से
बतियाने लगीं,
कुछ बूँदें छा गईं
मोर के फैले हुए पंखों पर
उषाकाल का इन्द्रधनुष बन कर।
तार पर झूलती हुई बूँदें
यह बताने के लिये ठहरी हैं
कि तुम जब गहरी नींद में थे
कोई उतरा था जमीं पर,
वह लुटा गया उन्हें
जो जागरण के मुहूर्त में
खड़े थे दोनों हाथ फैलाकर।
खेतों में नवांकुर,
उड़ान भरते पंछियों के समूह,
रम्भाती हुई गायें,
चौकड़ी भरते हिरण,
खिले हुए फूलों के बगीचे
सब वही बात दोहराना चाहते हैं
जो बताने के लिये ठहरी हैं
तार पर झूलती हुई बूँदें।

– मुरलीधर

विकसित भारत के लक्ष्य को समर्पित है बजट : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

किसानों, महिलाओं, गरीबों, युवाओं सहित सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान पर केन्द्रित है बजट

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के लक्ष्य को समर्पित केन्द्रीय बजट 2024-25 प्रस्तुत किया गया है। बजट में दैदिप्यमान भारत का भाव और महंगाई दर पर नियंत्रण की भावना स्पष्टतः परिलक्षित होती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषि उत्पादकता, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर पूरा बजट केन्द्रित है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी एक नई पहचान कायम करेगा। यह बजट मध्यप्रदेश को भी विकास के पथ पर कदम से कदम मिलाने का मौका देगा। विकसित भारत में ही विकसित मध्यप्रदेश की संभावना निहित है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मैं केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बधाई देना चाहता हूँ, जिनके माध्यम से महंगाई दर पर कन्ट्रोल करने की भावना है, वो परिलक्षित होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में चमक और महंगाई दर में स्थिरता हासिल की गई है। यह बजट भविष्य के विकास के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह बजट किसानों, महिलाओं, गरीबों, युवाओं सहित सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान पर केन्द्रित है।

रक्षाबंधन पर लाड़ली बहनों को 250 रुपए गिफ्ट करेगी सरकार

एक अगस्त को बैंक खातों में जमा होगी राशि ; नई आईटी पॉलिसी भी मंजूर

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश सरकार ने लाड़ली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं को रक्षाबंधन का गिफ्ट दिया है। 1 अगस्त को इन सभी महिलाओं के बैंक खातों में 250 रुपए जमा कराए जाएंगे। यह राशि लाड़ली बहना योजना के तहत मिलने वाले 1250 रुपए के अतिरिक्त होगी। यह फैसला मंगलवार को कैबिनेट बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में कहा, 'श्रावण मास शुरू हो चुका है। इसी माह राखी का त्योहार है इसलिए अगस्त की पहली तारीख को लाड़ली बहनों के खातों में 250 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे।'

मुख्यमंत्री ने कैबिनेट सदस्यों से कहा कि वे रक्षाबंधन पर 19 अगस्त को अपने विधानसभा क्षेत्रों में लाड़ली बहनों से राखी बंधवाएं। इस फैसले से सरकारी खजाने पर 324 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने नई आईटी पॉलिसी को भी मंजूरी दी है।

मार्केटिंग, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, पेटेंट फाइलिंग सहयोग करेगी सरकार

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, आईटी (सूचना एवं प्रौद्योगिकी) क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी बनाई गई है। सिंगल विंडो पॉलिसी के तहत मार्केटिंग, क्वालिटी सर्टिफिकेशन और पेटेंट फाइलिंग में सरकार पूरा सहयोग करेगी। निवेशकों को सस्ती दरों पर जमीन दी जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी जाएगी। बीपीओ बनाने पर किराए में और टैक्स में छूट दी जाएगी ताकि अधिक से अधिक निवेश आए।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 38.5 °c
न्यूनतम 33°c

सुबह सवेरे
इंदौर ■ बुधवार,24 जुलाई 2024

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

निर्मला ने पेश किया एनडीए सरकार का बजट

गरीबों, किसानों और महिलाओं के लिए खुला खजाना

- कौशल विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस
- 3 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री
- नई टैक्स रिजीम में 7.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री
- बिहार में बनेगा महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर
- बाढ़ से निपटने की भी तैयारी
- 20 लाख हुई मुद्रा लोन की लिमिट
- मिलेंगे नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और हाईवे,
- मोबाइल फोन और सोना-चांदी सस्ते होंगे
- आंध्र-बिहार के लिए खुले मोदी सरकार के भंडार,

निर्मला सीतारमण ने इतिहास रचते हुए लगातार 7वां केंद्रीय बजट पेश किया

नई दिल्ली। इंतजार की घड़ियां खत्म... मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट का पिटारा खुल गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का बजट रोजगार, कौशल विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर सहित 9 प्राथमिकताओं पर फोकस किया है।बजट भाषण के दौरान रोजगार से जुड़े कई अहम ऐलान किए गए। वहीं, बजट में इनकम टैक्स स्लैब में छूट देकर मध्यम वर्ग का दिल जीतने की कोशिश की गई है। इसके अलावा सबसे बड़े ऐलान के तहत कई जरूरी चीजों को सस्ता करने की भी घोषणा कर दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 7वीं बार बजट पेश किया। ऐसा लग रहा था निर्मला के मन से मंगलवार को मंगलमय बजट निकला। 3 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री, गरीबों, किसानों और महिलाओं के लिए खुला खजाना तो युवाओं के लिए नौकरी के दरवाजे खुले। अपने 1 घंटे 23 मिनट के बजट भाषण में युवा गरीब महिला और अन्नदाताओं को ध्यान मे रखते हुए विशेष नौ सूत्रीय योजनाओं का एलान किया। न्यू टैक्स रिजीम चुनने वाले करदाताओं को भी मामूली राहत दी है। साथ ही युवाओं और छात्रों के लिए भी योजनाओं की झड़ी लगा दी। बिहार को 58.9 हजार करोड़ और आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपये की मदद मुहैया कराने की घोषणा की है।

मोबाइल फोन और सोना-चांदी सस्ते होंगे, सरकार ने कस्टम ड्यूटी घटाई

बजट में इस बार सरकार ने मोटे तौर पर 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है और 2 की ड्यूटी बढ़ा दी है। इससे करीब 7 प्रोडक्ट सस्ते और 2 प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। सस्ते होने वाले प्रोडक्ट में मोबाइल फोन, कैंसर की दवाएं और सोना-चांदी है। वहीं प्लास्टिक से जुड़े प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं।

किस सेक्टर को क्या मिला

इनकम टैक्स- नई टैक्स रिजीम में बदलाव. सालाना 17,500 रुपये बचेंगे।

रोजगार- पहली नौकरी वालों को 15 हजार रुपये की मदद करेगी सरकार।
घर- पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ परिवारों को मिलेंगे घर।
शिक्षा- देश में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा।
किसान- कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित।
महिलाएं- महिलाओं-बालिकाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये।
हेल्थ- कैंसर की तीन और दवाओं को कस्टम ड्यूटी फ्री किया गया।
इंफ्रा- 11 लाख करोड़ का बजट. बिहार में दो एक्सप्रेस-वे और एक नया पुल बनेगा।

एजुकेशन लोन 10 लाख तक, ब्याज पर भी छूट

वित्त मंत्री ने घरेलू संस्थानों में हायर एजुकेशन के लिए लोन 10 लाख तक किए जाने भी ऐलान किया। घरेलू संस्थानों में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे।

खेती-किसानी में डिजिटल ढांचे को मजबूती

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार की कृषि, रोजगार और सामाजिक न्याय प्राथमिकताएं हैं। हमारी प्राथमिकताओं में शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा भी शामिल है। कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और क्षमता प्राथमिकता बेहद जरूरी है। दलहन-तिलहन की उत्पादकता और भंडारण बढ़ाएंगे। 30 फसलों की 109 किस्में जल्द मिलेंगी। हमारा लक्ष्य तिलहन उत्पादों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। कृषि में डिजिटल ढांचे को मजबूती देंगे, ताकि उत्पादकता बढ़ सके। 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे होगा।

किसान सम्मान निधि नहीं बढ़ेगी, एमएसपी पर कोई ऐलान नहीं- वित्त मंत्री ने खेती और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। यानी इस बार किसानों के लिए बजट 21.6 प्रतिशत यानी 25 हजार करोड़ रुपए बढ़ाया गया।

नौकरी और कौशल विकास पर 2 लाख करोड़ खर्च

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नौकरी, कौशल विकास और अन्य सुविधाओं पर 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये पैसे 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं लिए रोजगार के मौके बनाने और अन्य सुविधाओं पर खर्च किए जाएंगे।

युवाओं को इंटर्नशिप के लिए 5 हजार महीना मिलेगा

मोदी सरकार की 5वीं नई योजना के तहत 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार की इंटर्नशिप योजना से 1 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। पीएम मोदी का यह युवाओं के लिए स्पेशल इंटर्नशिप पैकेज है। इसके तहत युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप करने की मौका मिलेगा। साथ ही हर महीने 5 हजार रुपये का इंटर्नशिप भत्ता भी दिया जाएगा। इसके साथ ही जो युवा अपनी इंटर्नशिप पूरी कर लेते हैं उन्हें अलग से 6 हजार रुपये भी दिए जाएंगे। सरकार की इस योजना के तहत 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को लाभ पहुंचेगा।

कैंसर की तीन दवाएं सस्ती होने पर विशेषज्ञों ने की केंद्र की सराहना

कैंसर विशेषज्ञों ने मंगलवार को केंद्र सरकार द्वारा कैंसर की तीन और दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट देने के कदम की सराहना की। ये तीन दवाएं हैं- ट्रास्टुजुमैब डेरक्सटेकन (स्तन कैंसर के लिए), ओसिमर्टिनिब (ईजीएफआर म्यूटेशन के लिए फेफड़ों के कैंसर की दवा) और डुरवालुमैब (फेफड़ों और पित्त नली के कैंसर के लिए)। डेरक्सटेकन दवा का इस्तेमाल हर तरह के कैंसर में किया जा सकता है, जिसमें एचईईआरडब्ल्यू पॉजिटिव जीन हो। विशेषज्ञों ने सरकार की सराहना की।

एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर्स के लिए रोजगार से जुड़ी तीन स्कीम

पहली बार जॉब करने वालों के लिए स्कीम ए- पहली बार सभी फॉर्मल सेक्टर में वर्कफोर्स में प्रवेश करने वाले सभी एम्प्लॉइज को एक महीने की सैलरी मिलेगी। ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर होने वाले एम्प्लॉइज को एक महीने की सैलरी के बराबर राशि (15,000 रुपए से ज्यादा नहीं), तीन किस्तों में ट्रांसफर होगी। एलिजिबिलिटी लिमिट 1 लाख रुपए प्रति माह होगी। इस योजना से 210 लाख युवाओं को फायदा मिलने की संभावना है।
मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएशन के लिए स्कीम बी- पहली बार काम करने वाले एम्प्लॉइज के रोजगार से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एडिशनल एम्प्लॉयमेंट की योजना। एम्प्लॉयमेंट के पहले 4 साल में एम्प्लॉई और एम्प्लायर दोनों को उनके ईपीएफओ कॉन्ट्रीब्यूशन के अनुसार इंसेंटिव मिलेगा। इस योजना से 30 लाख युवाओं को फायदा मिलने की संभावना है।
एम्प्लॉयर्स के लिए स्कीम सी- यह एम्प्लॉयर फोकस्ड स्कीम सभी सेक्टर में एडिशनल एमप्लॉयमेंट को कवर करेगी। हर माह 1 लाख रुपए के वेतन के भीतर सभी एडिशनल एम्प्लॉयमेंट को गिना जाएगा। सरकार हर एक एडिशनल एमप्लॉई के लिए ईपीएफओ योगदान के लिए एम्प्लॉयर्स को दो साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का रीइंबर्समेंट करेगी।

प्राकृतिक खेती पर फोकस, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए और नौ प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार की जिसमें उत्पादकता बढ़ाना शामिल है। अपने बजट प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने कहा कि अगले 2 साल में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा खेती के लिए 32 क्षेत्रीय और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च उपज वाली और जलवायु लचीली किस्में जारी की जाएंगी। अगले 2 वर्षों में, 1 करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग द्वारा समर्थित प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा। पांच राज्यों में

जनसमर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 32 क्षेत्रीय और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च उपज वाली और जलवायु-लचीली किस्में किसानों द्वारा खेती के लिए जारी की जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना एक नीतिगत लक्ष्य होगा। सीतारमण ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सहकारी क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी। सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में कृषि में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) के कार्यान्वयन की सुविधा भी देगी।

म्यूचुअल फंड के एसआईपी इनवेस्टरों को बड़ा झटका

सरकार ने बढ़ाया रेट आफ इंट्रेस्ट

म्यूचुअल फंड के एसआईपी इनवेस्टरों के लिए बड़ा झटका लगा। लांग टर्म कैपिटल गेन यानी 2 वर्ष से अधिक समय तक रखी गई होल्डिंग यानि की म्यूचुअल फंड में लगाई इनवेस्टमेंट पर सरकार ने टैक्स बढ़ दिया है। म्यूचुअल फंड के इनवेस्टरों के लिए बड़ा झटका लगा। लांग टर्म कैपिटल गेन यानी 2 वर्ष से अधिक समय तक रखी गई होल्डिंग यानि की म्यूचुअल फंड में लगाई इनवेस्टमेंट पर सरकार ने टैक्स बढ़ दिया है। बता दें कि अभी तक टैक्स 10 प्रतिशत था जिसे अब बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं चुनिंदा असेट्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाकर 20 फीसदी किया गया है। इन घोषणाओं के चलते शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी जा रही है।

प्रतिक्रियाएं

युवाओं-मध्यम वर्ग को मिलेगी नई ताकतः पीएम

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया। बजट में किए गए प्रावधानों पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जताई

और कहा कि यह बजट देश को समृद्धि की ओर लेकर जाएगा और इस बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये शक्ति देने वाला बजट है। ये किसानों-युवाओं को प्रगति की राह पर ले जाना वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये उनकी आर्थिक प्रगति में निरंतरता का बजट है। ये युवाओं को अनगिनत मौके देने वाला बजट है।

यह कुर्सी बचाओ बजट है: राहुल गांधी

इसी बीच लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए इसे कुर्सी बचाओ बजट बताया है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बजट को सहयोगियों को खुश करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि ये बजट अपने मित्रों को खुश करने के लिए लाया गया है।

बजट में बिहार के लिए स्पेशल पैकेज पर बोले नीतीश कुमार हम तो विशेष दर्जा के लिए बोलते हैं

केंद्रीय बजट पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम बिहार को विशेष दर्जा दिलाने के लिए हम लगातार बोलते रहे। हमने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष मदद दीजिए जिससे राज्य आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि केंद्र से अगर अतिरिक्त मदद मिलेगी तो फायदा मिलेगा।

नकलची, 'सरकार बचाओ' बजट : खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को आरोप लगाया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की तरक्की वाला नहीं, बल्कि 'मोदी सरकार बचाओ' बजट पेश किया है। उन्होंने यह दावा भी किया कि यह 'नकलची बजट' है जिसमें सरकार कांग्रेस के 'न्याय' के एजेंडे की ठीक तरह से नकल नहीं कर पाई है।

रविशंकर प्रसाद

भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, यह(बजट) भारत के विकसित भारत होने के मार्ग को और मजबूत करेगा। रोजगार के लिए इसमें जो व्यापक रोडमैप बनाया गया है, वो बहुत अभिनंदनीय है...।

राकेश टिकैत

केंद्रीय बजट 2024 पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उन्हें (केंद्र को) यह बजट कागजों पर तो ठीक लगता होगा, लेकिन जमीनी स्तर पर इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है।

आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण का आर्थिक दस्तावेजः योगी

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के

आम बजट को लेकर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये बजट भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करेगा। आम बजट विकसित भारत-आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है।

बजट दिशाहीन, राजनीतिक मिशन वालाः ममता

कोलकाता- पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय बजट पर कहा कि यह बजट दिशाहीन है, इसमें कोई विजन नहीं है, सिर्फ राजनीतिक मिशन है।

इंदौर में बुजुर्ग ने खुद को गोली मारकर जान दी

सुसाइड से पहले बेटियों को मैसेज किया- परिवार को खुश नहीं रख पा रहा...

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर के विजय नगर में 65 साल के बुजुर्ग ने सोमवार रात खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। उन्होंने पलंग पर कमर की बल लेटकर 12 बोर की बंदूक से फायर किया। फायर से पहले बंदूक की नाल को गले पर रखा था। इससे गोली सिर के ऊपरी हिस्से से पार निकल गई। मौके पर ही मौत हो गई। शव को मंगलवार सुबह अस्पताल लाया गया है।विजय नगर पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग विजय शुक्ला ने लाइसेंसी बंदूक से फायर कर घर में ही सुसाइड किया है। फायर की आवाज सुनते ही छोटा बेटा, बहू और उनके तीनों बच्चे नीचे आए। फिर पुलिस बुलाई गई। सुसाइड से पहले इंदौर में ही रहने वाली दो बेटियों को मैसेज भी किया था। इसमें मौत के लिए खुद को जिम्मेदार बताया। लिखा कि वह परिवार को खुश रखना चाहता था लेकिन नहीं रख पा रहा है।

दो बेटे और चार बेटियां थीं, पत्नी की मौत हो चुकी

शुक्ला सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसी संचालित करते थे। फिर मालवा मिल पर दुकान भी खोली। पत्नी की मौत हो चुकी है। परिवार में दो बेटे और चार बेटियां हैं। चारों बेटियों की शादी इंदौर में ही की थी। बड़ा बेटा अहमदाबाद में नौकरी करता है। छोटा बेटा हेमंत उनके साथ ही छोटी बहू और तीन बच्चों के साथ रहती थी। छोटे बेटे ने शव को सबसे पहले देखा। सूचना मिलते ही इंदौर की चारों बेटियां और अहमदाबाद से बड़ा बेटा भी पहुंचा है। पिता के शव के पास बैठा बेटा। वह सदमे में है। सूचना पर पहुंची बड़ी बेटी भी पिता का शव देखकर बेहोश हो गई थी। काफी देर बाद उसे होश आया।

बेटे की दुकान पर बैठते थे शुक्ला

विजय शुक्ला ने कुछ समय पहले ही छोटे बेटे हेमंत के लिए मालवा मिल चौराहे पर दुकान खुलवाई थी। यह दुकान पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म-एसेसरीज से जुड़ी थी। रोजाना दोपहर में बेटे की इसी दुकान पर शुक्ला भी जाकर बैठा करते थे। घटना से पहले भी सोमवार शाम को ही वे दुकान से लौटे थे। खाना खाया और कुछ देर टहलने के बाद सोने चले गए। दो मंजिला मकान में शुक्ला अधिकतर समय नीचे के कमरे में ही रहा करते थे। सोमवार रात को बेटा हेमंत पिता के साथ बैठा। बातचीत के बाद पत्नी और बच्चों के साथ अपने कमरे में सोने चला गया। इसके बाद शुक्ला ने कमरे में खुद पर फायर कर लिया।

रोज मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, साइकिल से ही शहर में घूमते थे

विजय शुक्ला रोजाना जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाते थे। नियमित पूजा पाठ करने के बाद अपने काम से निकल जाते थे। वे साइकिल से ही चलते थे। पड़ोसियों ने किसी भी तरह के पारिवारिक विवाद से इनकार किया है। बड़ी बेटी के परिवार ने बताया कि पिता का मैसेज उसने काफी देर बाद देखा था। जैसे ही वह पिता के सामने पहुंची और शव देखकर बेहोश हो गई।

पत्नी की मौत से तनाव

परिवार ने बताया कि 6 साल पहले उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। अकेले रहने के चलते थोड़े तनाव में रहते थे। वक्त काटने के लिए अधिकतर समय बेटे हेमंत के बच्चों से बातचीत करते या फिर दुकान पर समय बिताते थे। पुलिस भी प्राथमिक तौर पर सुसाइड के पीछे डिप्रेशन को कारण मान रही है।

इंदौर के पिकनिक स्पॉट्स- वाटर फाल पर एंट्री बैन

इस मानसून सीजन तिंछा फाल, चोरल फाल, चोरल डेम, सीतलामाता फाल, कजलीगढ़ नहीं जा सकेंगे पर्यटक

इंदौर (एजेंसी)। मानसून सीजन में इंदौर और आसपास स्थित पिकनिक स्पॉट्स और वाटर फाल पर घूमने जाने वालों के लिए एक बुरी खबर है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर इंदौर जिले के जोखिम भरे और एकान्त पिकनिक स्पॉट्स और वाटर फाल पर जनता का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। कलेक्टर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में जन सामान्य के जीवन की सुरक्षा और हादसों की रोकथाम के लिए तिंछा फाल, चोरल फाल, चोरल डेम, सीतला माता फाल, कजलीगढ़, मेंहदी कुण्ड, जामन्या कुण्ड आदि पर्यटन स्थानों पर जोखिम भरे क्षेत्रों व एकान्त क्षेत्रों में जन सामान्य के प्रवेश को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी। आदेश के अनुसार महू तहसील क्षेत्रों में स्थित संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद द्वारा तत्काल उनके क्षेत्र में आने वाले पर्यटन क्षेत्र के आवश्यक स्थानों पर इस आशय के सूचना बोर्ड भी लगाए जाएंगे। निर्देश दिए गए हैं कि जहां आवश्यक हो, वहां सीमाएं भी निर्धारित की जाए। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे।

खजराना थाने से पुलिसकर्मी हिरासत में लेकर छोड़ा

भोपाल एसटीएफ की कार्रवाई, व्यापमं की परीक्षा में किया था फर्जीवाड़ा, नोटिस देकर भोपाल बुलाया

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर के खजराना थाने में पदस्थ जवान को एसटीएफ ने हिरासत में लिया गया। बाद में उसे नोटिस देकर छोड़ दिया गया। सिपाही को भोपाल बुलाया गया है। मंगलवार को भोपाल एसटीएफ ने यह कार्रवाई की है। पकड़े गए जवान का नाम पंकज है। बताया जा रहा है कि उसने व्यापमं द्वारा आयोजित परीक्षा में फर्जीवाड़ा किया था।

एसटीएफ को आशंका है कि पंकज ने उंगलियों के निशान में गड़बड़ी की है। इस मामले में एसटीएफ जांच कर रही थी। पंकज की भूमिका इस मामले में संदिग्ध मिली है। इस मामले में भोपाल में एफआईआर भी दर्ज

की गई। हालाकिं इंदौर के अफसरों के हस्तक्षेप के बाद भोपाल एसटीएफ को नोटिस देकर जाना पड़ा।

इंदौर में फर्जी टीआई ने टक्कर मारी, पिस्तौल से धमकाया

सीआरपीएफ का बर्खास्त सब इंस्पेक्टर ने रौब दिखाने पहनी वर्दी

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर में टीआई की वर्दी पहने एक शख्स ने स्कॉर्पियो से बाइक सवार को टक्कर मार दी। उसे पिस्तौल दिखाकर धमकाया और भाग निकला। बाइक सवार ने पुलिस को सूचना दी। फिर दोस्त के साथ स्कॉर्पियो का पीछा किया। थोड़ी दूर पर उसे बाइक अड़ाकर रोक लिया। वर्दी पहने शख्स ने गोली मारने की धमकी दी। इसी बीच पुलिस वहां पहुंच गई। थाने लाया गया तो आरोपी सीआरपीएफ का बर्खास्त सब इंस्पेक्टर निकला। मामला लसूड़िया थाना इलाके में सोमवार रात का है। पुलिस ने

बताया कि आरोपी गणेश पिता मोहनलाल परमार (40) निवासी जलालपुरा-देपालपुर ने रात करीब 8.30 बजे सुखलिया जा रहे संजय को टक्कर मार दी। संजय उठा और स्कॉर्पियो को रोका, लेकिन गणेश ने गाड़ी विजय नगर की तरफ तेजी से बढ़ा दी। संजय ने उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लिया और वहां मौजूद ट्रैफिक जवान को पूरा घटनाक्रम बताया। जवान ने विजय नगर पुलिस को वायरलेस पर सूचना दी।संजय अपने दोस्त के साथ स्कॉर्पियो का पीछा करने लगा। कुछ दूर जाकर गणेश की कार के आगे बाइक अड़ा दी। उसे बाहर निकालने लगे तो गणेश ने पिस्तौल तान दी। इसी बीच विजय नगर थाने के जवान भी पहुंच गए। उन्होंने आरोपी गणेश को पकड़ लिया।

वर्दी-पिस्टल देखकर पुलिस भी हैरान रह गई

टीआई की वर्दी और लोअर में गणेश को देखकर पुलिस जवान भी हैरत में पड़ गए। गणेश को थाने लाया गया।

पूछताछ में खुलासा हुआ कि गणेश रौब दिखाने के लिए थ्री स्टार लगी खाकी शर्ट पहनकर घूमता था। उसने संजय को डराने के लिए जो पिस्टल निकाली थी, वो एयर पिस्टल थी।

सीआरपीएफ से बर्खास्त किया चुका है आरोपी

डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि गणेश सीआरपीएफ का बर्खास्त सब इंस्पेक्टर है। उसका भाई भी सीआरपीएफ में है। गणेश ने जो वर्दी पहनी थी, वह उसके भाई की हो सकती है।

इंदौर के युगपुरुष आश्रम के संचालकों पर होगी एफआईआर!

सबूत मिटाने के आरोपों पर केंद्र की टीम करेगी अनुशंसा, सीएम-सीएस को भेजेंगे रिपोर्ट

इंदौर (एजेंसी)। युग पुरुष आश्रम में 10 बच्चों की मौत के मामले में अध्यक्ष, सचिव और संचालक को हटाने के बावजूद अब भी कई सवाल सुलग रहे हैं। बच्चों की मौत का सिलसिला जून के तीसरे हफ्ते में शुरू हो गया था, लेकिन छिपाया गया। इसके बाद अन्य बच्चे बीमार पड़ने लगे। उन्हें अपने बीमार होने से ज्यादा साथियों की मौत का खौफ था, क्योंकि एक के बाद एक की हालत बिगड़ रही थी। मामले में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं होने को लेकर सवाल उठे हैं। कानून के जानकारों का का कहना है कि आश्रम के कर्ताधर्ताओं ने सबूत मिटाए हैं। ऐसे में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दूसरी तरफ पीएमओ के निर्देश के बाद जांच में जुटी केंद्र की टीम भी सकते में हैं। यह टीम भी एफआईआर दर्ज करने की अनुशंसा करेगी। कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि अभी एफआईआर का कोई प्रावधान नहीं है। अगर शासन या किसी आयोग से दिशा-निर्देश मिलते हैं तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो हाई पावर कमेटी बनाई थी, उसका दायरा अभी के मामले को लेकर था।

बिना एफआईआर कैसे करेंगे तहकीकात

उधर, पीएमओ के निर्देश पर जांच में जुटी केंद्रीय टीम ने एफआईआर के मामले को गंभीरता से लिया है। टीम की सदस्य डॉ. दिव्या गुप्ता के मुताबिक संस्था के कर्ताधर्ताओं का हटाना ही केस का समाधान नहीं है। अब तहकीकात कैसे होगी, क्योंकि एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई। एफआईआर होगी तब ही तो तहकीकात शुरू होगी। इतना गंभीर मामला जिसमें अब तक 10 मौत की पुष्टि हो चुकी है उसमें एफआईआर होनी ही चाहिए। इसकी अनुशंसा की जानी थी। अगर जिला प्रशासन एफआईआर दर्ज नहीं करता तो केंद्र की टीम इसकी अनुशंसा करेगी।

स्कूलों में रिक्त पद भरने शिक्षकों की काउंसिलिंग

500 से अधिक टीचर्स ने माध्यमिक स्कूल का प्रभार लेने से मना किया

इंदौर (एजेंसी)। जिले के ढाई हजार प्राथमिक शिक्षकों में से 500 से अधिक ने उच्च पद का प्रभार लेने से मना कर दिया है। शिक्षकों की विभाग ने काउंसिलिंग आयोजित की थी। माध्यमिक स्तर के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करना है इसलिए ये सारी कवायद की जा रही है। इससे खाली पड़े पदों को भरा जाएगा।काउंसिलिंग के लिए संयुक्त संचालक लोक शिक्षण कार्यालय से सूची जारी की गई लेकिन इसमें गड़बड़ी थी। शिक्षकों के नाम छूट गए थे। उनके नाम के आगे विषय गलत लिख दिया था। इस पर शिक्षकों ने विरोध भी दर्ज करवाया था।सोमवार को काउंसिलिंग के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 29 प्राचार्य, व्याख्याता, सहायक ग्रेड 2 और 3 सहित कुल 50 से अधिक कर्मचारी लगाए गए। रात 12 बजे तक काउंसिलिंग चली।जिसमें करीब 2000 शिक्षकों को उच्च प्रभार दिया गया। उनके विषय के अनुसार अलग-अलग स्कूलों में प्रभार सौंपा गया है। करीब 500 शिक्षक ऐसे निकले जिन्होंने उच्च पद पर जाने से मना कर दिया है।

तीन तलाक के मामले में इंदौर हाईकोर्ट की टिप्पणी

'देश समान नागरिक संहिता की आवश्यकता को समझे, इससे अंधविश्वास और बुरी प्रथा पर लगेगी रोक'

इंदौर (एजेंसी)। तीन तलाक असंवैधानिक और समाज के लिए बुरा है। कानून निर्माताओं को यह समझने में कई साल लग गए। समय आ गया है कि अब देश समान नागरिक संहिता की आवश्यकता को समझे। समाज में आज भी आस्था और विश्वास के नाम पर कई कट्टरपंथी, अंधविश्वासी और अति-रूढ़िवादी प्रथाएं प्रचलित हैं। भारत के संविधान में पहले से ही अनुच्छेद 44 शामिल है जो समान नागरिक संहिता की वकालत करता है, लेकिन समय आ गया है कि अब इसे सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि वास्तविकता बनाया जाए। एक अच्छी तरह से तैयार समान नागरिक संहिता ऐसे अंध विश्वासों और बुरी प्रथाओं पर रोक लगाने का काम करेगी। इससे राष्ट्र की अखंडता को मजबूती भी मिलेगी।ये टिप्पणी मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंड पीठ ने तीन तलाक से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए की है।

क्या है मामला

दरअसल, बड़वानी जिले के राजपुर निवासी मुस्लिम महिला ने मुंबई निवासी पति, सास और ननद के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई थी। महिला के पति ने उसे तीन तलाक दिया था। महिला ने तीनों आरोपियों के खिलाफ तीन तलाक और दहेज प्रताड़ना की धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया था। जिसे निरस्त करने के लिए इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। कहा गया था कि तीन तलाक की धारा सिर्फ पति के खिलाफ लगाई जा सकती है सास और ननद के खिलाफ नहीं। वे इसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं।शासन की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट अमेय बजाज ने बताया कि कोर्ट ने तर्कों पर विचार करने के बाद सास और ननद के खिलाफ तीन तलाक की धारा में दर्ज अपराध को निरस्त

कर दिया है। उनके खिलाफ सिर्फ दहेज प्रताड़ना की धारा में केस चलेगा।

कोर्ट की ये है पूरी टिप्पणी

तलाक, मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। जो विवाह विच्छेद को दर्शाता है, जब एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक संबंध तोड़ देता है। मुस्लिम कानून के तहत सिर्फ तीन तलाक यानी तुरंत ही शादी के रिश्ते से मुक्ति अपरिवर्तनीय, जहां आदमी, केवल तीन बार तलाक शब्द बोल कर, अपनी शादी खत्म करने में सक्षम है। इस प्रकार का तात्कालिक तलाक कहलाता है। तीन तलाक, जिसे तलाक-ए-बिद्दत भी कहा जाता है। यह स्पष्ट है कि में तलाक-ए-बिद्दत या तीन तलाक, में शादी कुछ ही सेकंड के अंदर टूट सकती है। पति अगर गलती भी सुधारे तो महिला को ही हलाला के अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। शायरा बानो बनाम के प्रसिद्ध मामले में भारत संघ और अन्य (एआईआर 2017 एससी 4609) तीन तलाक की प्रथा पहले से ही है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा अवैध घोषित किया गया। तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाया गया है। ताकि मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को वैवाहिक न्याय और सुरक्षा मिले। तीन तलाक को कानून के रूप में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया। कहा गया कि ये आपराधिक कृत्य है। यह निश्चित रूप से समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है। कानून निर्माताओं को यह समझने में कई साल लग गए कि तीन तलाक असंवैधानिक और समाज के लिए बुरा है।हमें अब चाहिए कि देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता को समझें। और भी बहुत सारे निंदनीय, कट्टरपंथी, अंधविश्वासी हैं और समाज में प्रचलित अति-रूढ़िवादी प्रथाएं हैं। भारत का संविधान अनुच्छेद 44 पहले से ही समाहित है, जो समान नागरिक संहिता की वकालत करता है। नागरिकों के लिए इसे केवल कागजों पर नहीं बल्कि वास्तविकता बनने की जरूरत है। अच्छी तरह से तैयार समान नागरिक संहिता अंधविश्वास और कुप्रथाओं पर अंकुश लगाने का काम कर सकती है। ये राष्ट्र की अखंडता को सुदृढ़ करेगा।

एक छोटी बेटी है

2021 में दोनों की शादी हुई। एक छोटी बेटी है। पति का मुंबई में ही मोबाइल का बिजनेस है। शादी के कुछ समय बाद ही महिला ने बड़वानी आकर पति, सास और ननद के खिलाफ केस दहेज प्रताड़ना और तीन तलाक का केस दर्ज करवा दिया था। तभी हाईकोर्ट में सास और ननद की तरफ से याचिका लगाई गई थी। लंबे समय तक याचिका पेंडिंग रही। मामले में अब कोर्ट का फैसला आया है। तीन तलाक वाले केस से दोनों को मुक्त कर दिया है।

आश्रमों-होस्टलों को लेकर गाइड लाइन

कलेक्टर ने ली बैठक; साफ-सफाई, भोजन और सुरक्षा पर खास जोर

इंदौर (एजेंसी)। युग पुरुष की घटना के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने आश्रमों और होस्टलों संचालकों की बैठक ली। बैठक में साफ-सफाई, भोजन और सुरक्षा पर खास जोर दिया गया। इसके साथ ही कई बिंदुओं पर दिशा-निर्देश जारी किए गए। कलेक्टर निर्देश पर जिले के सभी सरकारी छात्रावासों और आश्रमों का नियमित रूप से निरीक्षण और बच्चों से संवाद होगा। छात्रावास और आश्रम के अधीक्षक संस्थाओं में साफ-सफाई, भोजन की गुणवत्ता और बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा पर विशेष ध्यान देंगे।

गाइड लाइन

- सभी अधीक्षक छात्रावासों औप आश्रमों के सभी स्टूडेंट्स से प्रतिदिन संवाद करें। उनमें यदि किसी भी प्रकार असुरक्षा का भाव आए तो समझकर उसका समय पर समाधान

किया जाए।
- अनुशासन का पालन करें और मुख्यालय पर ही रहे।
- अधीक्षक ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हो जो सिविल सेवा नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में आती हैं।
- बच्चों के लिए अधीक्षक/अधीक्षिका माता-पिता और गुरु की भूमिका में होते हैं। वे खुद को बच्चों के समक्ष एक मिसाल के रूप में स्थापित करें। कन्या छात्रावास/आश्रमों में अनिवार्यतः महिला चौकीदार ही रहे।
- छात्रावास/आश्रमों में बिजली के खुले तार नहीं हो। पेयजल या अन्य समस्याएं हो तो तत्काल सूचित कर दुरुस्त करवाएं।
- सुरक्षा के लिए सेफ्टी मस्ट सेफ्टी फर्स्ट भोजन बनाते समय अधीक्षक खुद उपस्थित रहे। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखे। छात्रावास/आश्रमों में निवासरत छात्र-छात्राओं से चर्चा में स्वास्थ्य, व्यक्तिगत और शरीर आदि की सफाई की स्थिति पर भी ध्यान दें। छात्र-छात्राओं का हर माह स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिमाह कराएं।
- छात्र-छात्राओं की सुरक्षा प्राथमिकता हैं। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न की जाएं। छात्रावास/आश्रमों में प्रकाश की व्यवस्था हो।
- पानी की टंकियों की नियमित साफ-सफाई करें। आरओ ठीक होकर पूर्णतः कार्यशील रहे। पालक समिति की बैठकें अनिवार्य रूप से आयोजित करें।
- बच्चों द्वारा ध्यान भटकाने वाली गतिविधि की जाने, अपनी परेशानी बताए जाने पर या बीमारी की स्थिति में तत्काल परिवार को

इंदौर में टेलर ने लगाई फांसी

टैंकर ड्राइवर की पत्नी ने भी खाया जहर, अस्पताल में तोड़ा दम

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर के एमआइजी इलाके में एक टेलर ने सुसाइड कर लिया। उसकी पत्नी पहले सावन सोमवार पर उज्जैन गई थी। वहीं बेटी ड्यूटी पर गई थी। दोपहर में टेलर अपनी मां के साथ घर पर था। वहीं गांधी नगर में भी एक टैंकर चालक की पत्नी ने जहर खाकर जान दे दी।एमआईजी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सोमनाथ की चाल में रहने वाले नरेन्द्र (50) पुत्र हीरा सिंह तोमर ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। वह सोमवार को घर पर अकेला था। बेटी खुशी ने

बताया कि पिता सिलाई का काम करते हैं। दो दिन पहले अपने मामा के यहां शादी से गांव से वापस आए थे। सोमवार को परिवार के लोग महाकाल दर्शन के लिए गए। इस दौरान पिता नरेन्द्र ने फंदा लगा लिया। नरेन्द्र पर किसी तरह के कर्ज और तनाव की बात से परिवार ने इनकार किया है।

टैंकर ड्राइवर की पत्नी ने दी जान

गांधी नगर के दिलीप नगर में रहने वाली सोना (30) पति मुकेश ने भी अपने घर में जहर खा लिया। पड़ोसियों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। सोना से परिवार के लोगों ने जहर खाने को लेकर पूछताछ की। लेकिन उसने किसी तरह का कारण बताने से इनकार किया। घटना के समय सोना के बच्चे स्कूल गए हुए थे। वहीं पति नौकरी पर गया हुआ था। पति गांव के सरपंच का टैंकर चलाता है।

निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरा कारीगर, मौत

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर के आजाद नगर में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से गिरने के चलते कारीगर की मौत हो गई। पुलिस ठेकेदार की लापरवाही को लेकर जांच कर रही है। आजाद नगर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गोल चौराहे के पास एक निर्माणाधीन मकान की तीसरी मंजिल से गिरने से शाहरुख निवासी मदीना नगर की मौत हो गई। वह मूल रूप से खंडवा का रहने वाला था। उसके साथ काम करने वाले रउफ ने बताया कि तीसरी मंजिल पर वह प्लास्टर कर रहा था। अचानक से बल्ली टूट गई। और वह नीचे आ गिरा। जिस मकान में घटना हुई। उसका ठेका अकरम नाम के ठेकेदार के पास था। शाहरुख उसके साथ ही काम कर रहा था।

संपादकीय

योगी को पीछे छोड़ते हिमंत

लगता है हिंदुत्व के एजेंडे पर अमल के मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने योगी आदित्यनाथ को भी पीछे छोड़ दिया है। असम सरकार की कैबिनेट ने 18 जुलाई को असम मुस्लिम विवाह और तलाक़ पंजीकरण अधिनियम एवं नियम, 1935 को ख़त्म करने के लिए एक विधेयक को मंज़ूरी दे दी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पुराने क़ानून को निरस्त करने के लिए एक विधेयक पेश करने की भी घोषणा की। 89 साल पुराने इस क़ानून को ख़त्म करने के बारे में असम सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय में बाल विवाह खत्म करने के साथ-साथ बहुपत्नी प्रथा को भी रोकना है। असम सरकार अपने इस फ़ैसले को प्रगतिशील क़दम बता रही है। वहीं मुस्लिम परिवारों में इस क़दम को आशंका के साथ देखा जा रहा है। चिंता उन लोगों में ज्यादा है, जिनके बाल विवाह काफी पहले हो चुके हैं। ऐसे मुस्लिम परिवारों में डर है कि नए कानून की आंच उन तक भी आ सकती है। जहां तक बाल विवाह का सवाल है तो पहले तो यह प्रथा सभी धर्मों के लोगों में प्रचलित थी। 12-13 साल की किशोरियों का विवाह कर दिया जाता था, जो न ठीक से शारीरिक रूप से विकसित हो पाती थीं और न ही यौन सम्बंधों और पारिवारिक जिम्मेदारी के बारे में उन्हें कुछ समझता था। असम में यह कानून लाने की चर्चा फरवरी से चल रही थी। मुख्यमंत्री हिमंत के अनुसार नए कानून में मुस्लिम विवाह का पंजीकरण सरकारी कार्यालयों में होगा। विवाह की जो सही उम्र है उसी के हिसाब से नए क़ानून में पंजीयन होगा। पूर्ववर्ती कानून में बाल विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल थे, भले ही दूल्हा और दुल्हन 18 और 21 वर्ष की क़ानूनी उम्र तक नहीं पहुंचे हों, जैसा कि क़ानून में आवश्यक है। सरकार ने राज्य में 94 मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार यानी सरकारी क़ाज़ी के कामकाज को भी ख़त्म कर दिया है। कहने को यह सरकार का प्रगतिशील कदम है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि इससे मुस्लिमों की दिक्कतें बढ़ेंगी। क्योंकि कानून का टारगेट वही हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील ए.आर. भुइयां का तर्क है कि अगर किसी क़ानून में कोई कमी है तो उसमें संशोधन किया जा सकता था। मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937 के हवाले से वो कहते हैं कि शरीयत क़ानून की धारा 2 में बताया गया है कि भारत में शरिया क़ानून के कौन-कौन से विषय को मान्यता मिलेगी। इसमें मुस्लिम विवाह और तलाक़ की बात भी कही गई है। 'संसदीय क़ानून उसी शरिया लॉ के आधार पर बने हैं। शरिया लॉ में जब एक लड़की को मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं तो उसे बालिग़ मान लिया जाता है। भले ही मुख्यमंत्री सरमा इस अधिनियम को निरस्त करने के पीछे मुस्लिम समाज में बाल विवाह को समाप्त करने की दलील दे रहे हैं, लेकिन जानकार इसे नई राजनीतिक और साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की चाल मान रहे हैं। सीएम सरमा का तर्क है कि राज्य में 80 फ़ीसदी बाल विवाह अल्पसंख्यक समुदाय में ही हैं। हमारे लिए यह समस्या धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक है। 2011 की जनगणना के मुताबिक़, असम में 34 फ़ीसदी आबादी मुसलमानों की है, जो राज्य की कुल जनसंख्या 3.12 करोड़ में से 1.06 करोड़ है। राज्य में प्रत्येक 10 साल में मुसलमानों की आबादी 16 फ़ीसदी बढ़ रही है। इस लिहाज़ से 2051 तक असम मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा।' बाल विवाह किसी भी समाज में हों, रूकने चाहिए, लेकिन हिंमत सरकार का असली उद्देश्य हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण कराना है, जो कितना सफल होगा, यह आने वाले चुनावों में पता चलेगा।

नजरिया

राम पुनियानी

लेखक आईआईटी मुंबई में शिक्षक रहे हैं और सन् 2007 के नेशनल कम्यूनल हार्मोनी अवॉर्ड से सम्मानित हैं।

अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरदेनिया

असुरक्षा का भाव चमका रहा है बाबाओं का धंधा

उत्तरप्रदेश के हाथरस जिले में भगदड़ में कम से कम 121 लोग मारे गए. इनमें से अधिकांश निर्धन दलित परिवारों की महिलाएं थीं. भगदड़ भोले बाबा उर्फ़ नारायण साकार हरी के सत्संग में मची. भोले बाबा पहले पुलिस में नौकरी करता था. बताया जाता है कि उस पर बलात्कार का आरोप भी था. करीब 28 साल पहले उसने पुलिस से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और बाबा बन गया. कुछ साल पहले उसने यह दावा किया कि वह कैंसर से मृत एक लड़की को फिर से जिंदा कर सकता है. जाहिर है कि ऐसा कुछ नहीं हो सका. बाद में बाबा के घर से लाश के सड़ने की बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस से शिकायत की. इस सबके बाद भी वह एक सफल बाबा बन गया, उसके अनुयायियों और आश्रमों की संख्या बढ़ने लगी और साथ ही उसकी संपत्ति भी.

हालिया घटना के बाद बाबा के कुछ चेले-चपाटों को पुलिस द्वारा आरोपी बनाया गया है. मगर बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है. भगदड़ इसलिए मची क्योंकि यह प्रचार किया गया था कि जिस मिट्टी पर बाबा चलता है, वह बहुत से रोगों को ठीक कर सकती है. सत्संग ख़त्म होने के बाद बाबा जब वापस जा रहा था तब जिस मिट्टी पर उसके कदम पड़े थे, उसे उठाने के लिए भक्तगण लपके जिससे भगदड़ मच गयी और बड़ी संख्या में लोग अपनी जान से हाथ खो बैठे. यह बाबा कितना लोकप्रिय हैं यह इससे जाहिर है कि सत्संग में 80,000 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति दी गयी थी मगर वहां करीब डेढ लाख लोग पहुँच गए.

भारत में बाबा कोई नई चीज़ नहीं हैं. और ऐसा भी नहीं है कि बाबा केवल भारत में पाए जाते हैं. हाँ यह ज़रूर है कि पिछ्ले कुछ सालों से उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है. भारत में सैकड़ों बाबा हैं और वे देश के हर हिस्से में पाए जाते हैं. कुछ बाबाओं की ख्याति विशिष्ट क्षेत्रों में है. आसाराम बापू और गुरमीत राम रहीम इंसान जैसे कुछ बाबा बलात्कार और हत्या करने के कारण जेलों की हवा खा रहे हैं. एक अन्य सफल बाबा हैं बाबा रामदेव, जिन्हें आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का मज़ाक उड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जम कर फटकार लगाई थी. श्री श्री रविशंकर पर यमुना नदी को प्रदूषित करने का आरोप है. जग्गी वासुदेव के कई आश्रमों में आपराधिक गतिविधियाँ होने के चर्चा है. बाबा अलग-अलग प्रकार के हैं मगर कुछ बातें सभी बाबाओं में समान हैं. सभी बाबाओं के पास ढेर सारी संपत्ति और धन है, सभी बाबा अंधश्रद्धा को बढ़ावा देते हैं और सभी का आत्मविश्वास अचंभित करने वाला है.

यद्यपि इस बारे में कोई पक्की जानकारी तो उपलब्ध नहीं है मगर मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि बाबाओं की संख्या और उनके प्रभाव में पिछले कुछ दशकों में तेजी से वृद्धि हुई है. इस वृद्धि का धर्म की

राजनीति के बढ़ते बोलबाले से अंतर्संबंध स्थापित करना भी आसान नहीं है. यह सही है कि दूसरे देशों में भी बाबाओं की तरह के लोग हैं. अमरीका में केरिसमेटिक ईसाई आन्दोलन है तो कुछ मुस्लिम देशों में भी चमत्कार करने वाले फ़क़ीर हैं. मगर भारत में बाबाओं का जितना प्रभाव है, उतना किसी और देश में नहीं है. सारे बाबा धर्म का चोला ओढ़े रहते हैं. वे संस्थागत हिन्दू धर्म के पुरोहित वर्ग से नहीं होते. उनमें से अधिकांश अपने बल पर सफलता हासिल करते हैं. वे लोगों का दिमाग पढ़ने और अपने अनुयायियों की कमजोरियों का फायदा उठाने में सिद्धहस्त होते हैं.

मगर एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि लोग आखिर बाबाओं की ओर आकर्षित क्यों होते हैं? निसंदेह, बाबा अपनी मार्केटिंग बहुत बढ़िया ढंग से करते हैं मगर यह भी सही है कि उनके भक्तों की अपनी कमजोरियां होती हैं जिनके चलते वे इन धोखेबाजों के चंगुल में फँस जाते हैं. इनमें से कई ऐसे होते हैं जो गंभीर समस्याओं से जूझ रहे होते हैं. उनकी समस्यायों का कोई हल उनके पास नहीं होता. उन्हें दरकार होती है सांत्वना के कुछ शब्दों की, किसी ऐसे व्यक्ति की जो उन्हें यह भरोसा दिला दे कि बाबा की चरणरज माथे से लगाने से, उनके प्रति पूर्ण समर्पण से या उनके बताए उपाय करने से उसकी समस्या हल हो जाएगी. बाबाओं के आसपास जो भीड़ जुटती है, उनमें बहुसंख्या ऐसे लोगों की होती है जो असुरक्षित महसूस कर रहे होते हैं. राजनेताओं से सांठगाँठ भी उनकी सफलता में योगदान देती है. गुरमीत राम रहीम महीनों पर पैरोल पर रहता है, विशेषकर चुनावों के समय. हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर अपनी पूरी मंत्रीपरिषद के साथ गुरमीत का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे.

परन्तु मुख्यतः अनुयायियों में असुरक्षा का भाव उन्हें बाबाओं की ओर आकर्षित करता है. जितनी ज्यादा असुरक्षा, बाबाओं के प्रति उतनी ज्यादा श्रद्धा. और जितनी ज्यादा श्रद्धा, विवेक और तार्किकता से उतनी ही दूरी. असुरक्षा का कारक कितना महत्वपूर्ण है यह हम इससे भी समझ सकते हैं कि जिन देशों में आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा कम है, वहां धर्म का प्रभाव भी कम होता जा रहा है. वैश्विक शोध संस्थान पीईडब्ल्यू का निष्कर्ष है- 'इस मामले में संयुक्त राज्य अमरीका अकेला नहीं है. पश्चिमी यूरोप के देशों के नागरिक सामान्यतः अमरीकियों से भी कम धार्मिक हैं क्योंकि वे उस राह पर अमरीका से कई दशक पहले चल पड़े थे. धर्म का घटता प्रभाव आर्थिक दृष्टि से उन्नत अन्य देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी देखा जा सकता है.'

मिशिगन विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर पोलिटिकल स्टडीज के प्रोफेसर रोनाल्ड इंगोहार्ट अपनी पुस्तक 'गिविंग अप ऑन गॉड' (पृष्ठ 110-111) में लिखते हैं, 'सन् 2007 से लेकर 2019 तक जिन 49 देशों का हमनें अध्ययन किया, उनमें से 43 में उस अवधि में लोगों में धार्मिकता घटी है. धार्मिक आस्था में कमी केवल उच्च आय वाले देशों तक सीमित नहीं है. ऐसा पूरी दुनिया में हुआ है. ऐसे लोगों की संख्या बढती जा रही है जिन्हें नहीं लगता कि उनके जीवन को अर्थपूर्ण बनाने और उन्हें सहारा और संबल देने के लिए धर्म ज़रूरी है. लम्बे समय से यह कहा जाता रहा है कि अमरीका इस बात का प्रमाण है कि आर्थिक रूप से उन्नत देश भी अत्यंत धार्मिक हो सकता है. मगर अन्य धनी देशों की तरह, अमरीका भी अब धर्म से दूर जा रहा है.'

बाबाओं के साम्राज्य से निपटना आसान नहीं है. हमारे संविधान के भाग चार के अनुच्छेद 51क (मौलिक कर्तव्य) में यह शामिल है कि 'भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद, और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे.' बाबा और उनके संरक्षक इस प्रावधान का खुलेआम उल्लंघन करते हैं.

देश में कई ऐसे सामाजिक समूह हैं जो बाबाओं का पर्दाफाश कर उनका विरोध करते रहे हैं. इनमें हवा से राख पैदा करने और आग पर चलने जैसे 'चमत्कारों' की असलियत लोगों के सामने रखना शामिल हैं. महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ऐसी ही संस्था है. उससे जुड़े डॉ नरेन्द्र दाभोलकर को सनातन संस्था की तरह के दकियानूसी समूहों के कार्यकर्ताओं ने क्रूरतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया था. इसी तरह की ताकतों ने कामरेड गोविन्द पंसारे, गौरी लंकेश और प्रोफेसर कलबुर्गी की हत्या की. डॉ दाभोलकर की हत्या के बाद, महाराष्ट्र विधानसभा ने अंधश्रद्धा और चमत्कारिक इलाज के खिलाफ एक कानून पारित किया.

पूरे देश में ऐसे कानूनों की ज़रुरत है. हमें वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना होगा. साथ में हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा हासिल हो. वर्तमान व्यवस्था, जिसमें अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब को हमें बदलना होगा. हमें महात्मा गाँधी के दिखाए रास्ते पर चलते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी नीतियां अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाई जाएँ. तभी हम समाज में सुरक्षा का भाव स्थापित कर सकेंगे.

केंद्र का निर्णय

लोकेन्द्र सिंह

लेखक स्तंभकार हैं।

सरकार ने की सरकारी कर्मचारियों के मौलिक अधिकार की रक्षा

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में कर्मचारियों के शामिल होने पर लगे प्रतिबंध को हटाकर नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा की है। अब कर्मचारी संघ की गतिविधियों में सामान्य नागरिकों की भाँति शामिल हो सकेंगे। निःसंदेह, सरकार का यह निर्णय लोकतंत्र और संविधान की भावना को मजबूत करने वाला है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह विविध सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संगठनों में शामिल हो सके। एक सामान्य नागरिक की भाँति यह अधिकार कर्मचारियों को भी प्राप्त है कि अपने कार्यालयीन समय के बाद सामाजिक गतिविधियों का हिस्सा हो सकते हैं। परंतु, लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना को कमजोर करते हुए तत्कालीन सरकार ने 58 वर्ष पहले 1966 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इतना ही नहीं, सरकारी कर्मचारी के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई का विधान भी रखा गया था। यह एक प्रकार से राष्ट्रीय विचार के प्रति झुकाव रखनेवाले लोगों को हतोत्साहित करने का प्रयास ही था।

इस तानाशाही एवं द्वेषपूर्ण निर्णय का उत्तर संघ ने तो कभी नहीं दिया लेकिन समाज ने अवश्य ही आईना दिखाने का कार्य किया। संघ को दबाने एवं समाप्त करने के लिए अनेक प्रयत्न किए हैं। इस आदेश के अतिरिक्त तीन बार पूर्ण प्रतिबंध भी लगाया। संघ की छवि खराब करने के लिए बड़े-बड़े नेताओं की ओर से मिथ्या प्रचार भी किया गया। अपने समर्थक बुद्धिजीवियों से पुस्तकें भी लिखवायी गईं। लेकिन संघ विरोधियों के ये सब प्रयास विफल ही रहे। निस्वार्थ भाव से देश और समाज के लिए कार्य करनेवाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोई रोक नहीं सका। अपनी 99 वर्ष की यात्रा में संघ ने लगातार प्रगति एवं विस्तार ही किया है। अपने विचार, आचरण एवं सेवाकार्यों से संघ ने समाज का विश्वास जीता, जिसके कारण समाज सदैव संघ के साथ खड़ा रहा।

कई ऐसे उदाहरण हैं, जिनमें संघ गतिविधि में शामिल होने पर सरकारों ने सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की। लेकिन वे सभी मामले न्यायालय में टिक नहीं सके। संघ के स्वयंसेवक न्यायालय से जीतकर आए। उनकी छोटी-छोटी जीतों की श्रृंखला ने भी यह साबित किया कि संघ की गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए लगाया गया तत्कालीन सरकार का आदेश संविधान एवं मौलिक अधिकारों की मूल भावना के विरुद्ध था। इस प्रतिबंध को 1966 के बाद से ही चुनौती मिलने लगी थी। क्योंकि संघकार्य को बाधित करने और स्वयंसेवकों को प्रताड़ित करने की जिस मंशा से सरकार ने यह प्रतिबंध लगाया था, उसे अंजाम देने का कार्य देशभर में शुरू किया गया। इस प्रतिबंध को हथियार बनाकर सरकारों ने देश के विभिन्न राज्यों में संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं की नौकरी छीनना शुरू कर दिया। सरकार की मनमानी को स्वयंसेवकों ने न्यायालयों में चुनौती दी, जहाँ सरकारों को मुंह की खानी पड़ी। मैसूर उच्च न्यायालय ने वर्ष 1966 में रंगनाथचार अग्निहोत्री की याचिका पर निर्णय देते हुए कहा था कि प्रथम दृष्ट्या आरएसएस एक गैर-राजनैतिक एवं सांस्कृतिक संगठन है जो कि गैर-हिंदुओं के प्रति किसी भी द्वेष अथवा घृणा की भावना से मुक्त है। इसी क्रम मे न्यायालय ने आगे कहा कि संघ ने भारत में लोकतांत्रिक पद्धति को स्वीकार किया है। अतः राज्य सरकार द्वारा याची को सेवा से हटाने का निर्णय गलत है। इसके साथ ही न्यायालय ने उक्त कर्मचारी को सेवा में बहाल करने का निर्णय सुनाया। इसी प्रकार, वर्ष 1967 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के कर्मचारी रामपाल को पद से हटाने संबंधी आदेश को रद्द करते हुए कहा कि संघ कोई राजनैतिक संगठन नहीं है, अतः इसकी गतिविधियों में भागीदारी करना कानूनी रूप से गलत नहीं है। ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार द्वारा रामपाल को पद से इस आधार पर हटाया गया था कि वे आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेते हैं एवं राज्य की दृष्टि में आरएसएस एक राजनैतिक संगठन है। 'भारत प्रसाद त्रिपाठी बनाम मध्यप्रदेश सरकार तथा अन्य' प्रकरण में तो 1973 में मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय ने यहाँ तक कह दिया कि 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी कार्यक्रम में भाग लेने के आधार पर किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं की जा सकती। किसी अंतरस्थ हेतु जारी किया गया (इस आशय का) कोई आदेश वैध नहीं ठहराया जा सकता'। यानी न्यायालय ने संघ की गतिविधि में शामिल होने से रोकने के लिए लगाए गए किसी भी प्रतिबंध/आदेश को अवैध करार दिया। इसके अलावा 'मध्यप्रदेश राज्य बनाम राम शंकर रघुवंशी तथा अन्य (1983)', मामले में उच्च न्यायालय, 'श्रीमती थाट्टुमकर बनाम महाप्रबंधक टेलीकम्यूनिकेशन्स, केरल मंडल (1982)' मामले में अर्नाकुलम स्थित केरल उच्च न्यायालय और 'डीबी गोहल बनाम जिला न्यायाधीश, भावनगर तथा अन्य (1970)' मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने यही निर्णय दिए कि संघ से जुड़े होने या उसके कार्यक्रमों में शामिल होने के आधार पर किसी कर्मचारी पर न तो कार्रवाई की जा सकती है और न ही उन्हें सेवा से हटाया जा सकता है।

कुछ प्रकरण ऐसे भी हैं, जिनमें संघ के कार्यकर्ताओं को इस प्रतिबंध के लागू होने से पहले ही निशाना बनाया गया। इन मामलों से स्पष्ट है कि तत्कालीन सरकारें शुरू से ही चाहती थीं कि संघ के कार्यक्रमों में शामिल होनेवाले लोगों के मन में भय उत्पन्न किया जाए। ताकि हिन्दुओं के संगठन के कार्य को रोका जा सके। परंतु, न्यायपालिका से लेकर आमजन की कसौटी पर राष्ट्रीय विचार को कमजोर करने के सभी प्रयास विफल रहे। 'कृष्ण लाल बनाम मध्यभारत राज्य (1955)' में इंदौर स्थित मध्यभारत उच्च न्यायालय, 'चिंतामणि नुरगांवकर बनाम पोस्ट मास्टर जनरल, कें.मं., नागपुर (1962)' में बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर न्यायपीठ, 'जयकिशन महरोत्रा बनाम महालेखाकार (1963)' में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, 'केदारलाल अग्रवाल बनाम राजस्थान राज्य तथा अन्य (1964)' मामले में जोधपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय और 'मनोहर अंबोकर बनाम भारत संघ तथा अन्य (1965)' प्रकरण में दिल्ली स्थित पंजाब उच्च न्यायालय ने यही कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गैरकानूनी संगठन नहीं है। सरकारी कर्मचारी को संघ के कार्यक्रमों में भाग लेने के आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता। यदि कोई सरकारी कर्मचारी संघ का सदस्य है तब भी उसे इस आधार पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता। स्मरण रखें कि वर्ष 1932 में अंग्रेजों ने भी सरकारी कर्मचारियों के संघ से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अंग्रेजी हुकुमत की ओर से जारी परिपत्र में आदेश दिया गया कि 'सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य बनने अथवा उसके कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति नहीं रहेगी'। कहा जा सकता है कि सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने से रोकने के लिए जिस प्रकार का प्रतिबंध कांग्रेस सरकार ने लगाया, वह औपनिवेशिक काल की अंग्रेजों की नीति को ही आगे बढ़ाने का कार्य था।

बाद के वर्षों में जब राज्यों में राष्ट्रीय विचार का पोषण करनेवाली सरकारें आईं तो उन्होंने लोकतंत्र एवं मौलिक अधिकार विरोधी इस प्रतिबंध को राज्यों में समाप्त कर दिया। संघ ने इस प्रतिबंध की कभी चिंता नहीं की क्योंकि न्यायालयों में इस तुगलकी फरमान के घुटने इतने अधिक छिल गए थे कि यह स्वतः ही निष्प्रभावी हो गया था। फिर भी, वर्ष 2000 में जब संघ के तत्कालीन सरसंघचालक प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह 'रज्जू भैया' से पूछा गया कि संघ इस प्रतिबंध को लेकर क्या सोचता है? तब उन्होंने कहा था कि संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगाने अथवा हटाने की कार्यवाही में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसके निर्णय का अधिकार सरकारों के पास है। उल्लेखनीय है कि गुजरात सरकार ने इस दिशा में सबसे पहला कदम उठाया। बाद में उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्यप्रदेश की सरकारों ने भी प्रतिबंध को हटा लिया। यह प्रतिबंध केवल केंद्र सरकार में रह गया था, उसे भी वर्तमान केंद्र सरकार ने संघ के हस्तक्षेप के बिना, स्वतः ही समीक्षा करने के बाद हटा लिया है। केंद्र सरकार के निर्णय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से भी संतुलित टिप्पणी की गई है। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा- 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण एवं समाज की सेवा में संलग्न है। राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता-अखंडता एवं प्राकृतिक आपदा के समय में समाज को साथ लेकर संघ के योगदान के चलते समय-समय पर देश के विभिन्न प्रकार के नेतृत्व ने संघ की भूमिका की प्रशंसा भी की है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक संगठन की गतिविधियों में भाग लेने के लिए निराधार ही प्रतिबंधित किया गया था। शासन का वर्तमान निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला है'। कहना होगा कि वैसे तो इस प्रतिबंध का कोई औचित्य नहीं रह गया था लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने इसे हटाकर अच्छा ही किया। इससे आमजन के ध्यान में यह भी आया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने किस प्रकार राष्ट्रीय विचारधारा के दबाने का प्रयास किया। आज जब संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की बहस चल रही है, तब भी उन्हें ध्यान आएगा कि किन सरकारों ने संविधान की मूलभावना के विरुद्ध कार्य किया।

कटाक्ष

डॉ. प्रदीप मिश्र

मूल-नक्षत्र में पैदा हुई मच्छर कन्या

दाई ने खबर दी कि श्रीमती मच्छर ने कन्या को जन्म दिया है। समूची नाली में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। मच्छर खानदान में बड़े दिनों के बाद खुशियाँ आईं थीं - कन्या ने जन्म लिया था। मच्छरों के काटने से हिजड़ा बने इंसान, सोहर गा रहे थे, जायो मच्छरिया ने लल्ली/ सज गए नाले और नल्ली।

मच्छर, इंसानों से ज्यादा सभ्य हैं। उनकी सोसायटी में कन्या-भ्रूण हत्या की कोई प्राब्लम नहीं बल्कि उसके जन्म लेने पर तो वे खुशियाँ मनाते हैं। पुरुष मच्छर तो निकम्मे होते हैं - अरे मर्द होकर किसी का खून न चूस सको, मलेरिया-डेंगू न फैला सकोज धित्कार है ऐसी जिन्दगी पर। मच्छरों में असली मर्द तो उनकी महिलाएं होतीं हैं। वे ही इंसानों का खून चूसतीं हैं और तरह-तरह की बीमारियाँ फैलाकर, अपनी कौम का नाम रौशन करतीं हैं।

खानदानी पंडितजी ने कुंडली बनाने के लिए पोथी खोली और गंभीर मनन करने के बाद चुप्पी तोड़ी,' कन्या का जन्म मूल-नक्षत्र में हुआ है। यह यशस्विनी होगी। इसके दंश की चर्चा एवं प्रभाव अखिल-विश्व में होगा। यह जिस इंसान को काटेगी उस पर तत्काल मारकेश लगेगा और वह डेंगू नामक रोग से ग्रसित हो जाएगा। हकीम समय रहते इसका इलाज नहीं कर पाएंगे और इसका फैलाव रोकने में नाकाम, हाकिमों की नौकरी साँसत में पड़ जाएगी। और जब तक कोई कुछ समझेगा मत्यु, रोगी का वरन् कर लेगी। बच्ची अपनी परदादी श्रीमती एनाफिलीज से भी आगे जाएगी।'

कन्या की दादी ने नवजात के भविष्य प्रति चिंता व्यक्त की,' पंडितजी, इस समय देश में बड़ी सफाई चल रही है। पानी को कहीं नहीं रुकने दिया जा रहा है। नालियों में दवाई डालकर मच्छरों का विनाश किया जा रहा है। बिटिया का जीवन, संकट में तो नहीं पड़ेगा?'

-'अनावश्यक चिंता तनिक न पालें। जब तक हमारे यशस्वी नेता, यशवंत अफसर और यशस्विनी जनता रहेगी, यकीन मानिए गुटखा, गढ्ढे और गंदगी, चिर-स्थाई रूप से रहेंगे। मुझे दिख रहा है कि यह बिटिया ही नहीं बल्कि इसकी आने वाली कई पीढ़ियाँ भी इसी तरह फूलेंगी-फलेंगी और अपने वंश को गौरवांवित करेंगी।'

फिर पंडितजी ने अपना पोथी-पत्रा समेटा और पड़ोसी मच्छर-परिवार की तरफ निकल लिए, सुना है वहाँ भी डेंगू फैलाने वाली मच्छर-कन्या ने जन्म लिया है।

सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पी.जी. इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेस प्रा. लि., राउखेड़ी, देवास रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 662, साईं कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक - उमेश त्रिवेदी
संपादक (म.प्र.) - गिरीश उपाध्याय
वरिष्ठ संपादक - अजय बोकिल
स्थानीय संपादक - हेमंत पाल
प्रबंध संपादक - अरुण पटेल

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

जवाहर चौधरी

लेखक व्यंग्यकार हैं।

ठीकरे मांग रहे सिर

हारने के बाद हार का ठीकरा सामने आता है। हार जितनी बड़ी होती है ठीकरा भी उतना बड़ा होता है। परंपरा ये है कि जितनी जल्दी हो किसी के सिर पर ठीकरे को फोड़ देना जरूरी है। आदर्श राजनीति में चाकू पीठ में ही घोंपा जाता है, उसी तरह ठीकरा सिर के अलावा और कहीं नहीं फोड़ा जा सकता है। ठीकरा कोई तिजोरी में रखने की चीज नहीं है, न ही पार्टी कार्यालय में मोमेंटो यानी स्मृति चिन्ह की तरह सजाया जा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि ठीकरा चाहे जहां फोड़ा भी नहीं जा सकता है। उसके लिए बाकायदा एक सिर लगता है, यानी एक बाजिब सिर। ये नहीं कि किसी रास्ते चलते को पकड़ लिया और उसके सिर पर फोड़ दिया दन्न से। पुराने जमाने में अध्यक्ष के सर को यह सम्मान दिया जाता था, जिस पर नारियल से ले कर ठीकरा तक, सब कुछ फोड़ा जा सकता था। लेकिन हाल के बरसों में कुछ गलतफहमियों ने जड़े जमा लीं। अध्यक्ष के गले में पड़ने वाली मालाओं का ध्यान रहा, ठीकरों को भूल गए। अगर दूरदृष्टि से जोखिम का ध्यान रखा होता तो न सही अध्यक्ष, कम से कम उपाध्यक्ष तो किसी शोषित-पीड़ित बेनाम कार्यकर्ता को बनाया होता तो आज आराम से काम आ गया होता। जिसने दस साल से अपने सिर पर सब कुछ लिया, अगर उसी को जरा सा श्रेय देते तो वह ठीकरे भी अपने सिर पर फुड़वा लेता। अब क्या हो सकता है, गलती हो गई। ठीकरे हर राज्य से थोक में चले आ रहे हैं। पार्टी कार्यालय का पिछ्वाड़ा गोदाम की तरह ठीकरों से भर गया है। जो अपनी गरदन तक भेजने का दावा कर रहे थे अब ठीकरे भेज रहे हैं। इधर जिन्होंने सारी शक्तियां एक जगह केन्द्रित करके रखी हुई थी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ठीकरों का विकेन्द्रीकरण कैसे हो ! लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता। ठीकरे मुंडेर पर उगे पीपल की तरह रोज बढ़ते जा रहे हैं। समस्या ये है कि यदि समय रहते इन्हें किसी सिर पर नहीं फोड़ा गया तो ये ईंट ईंट बिखेर देंगे।

पार्टी के कुछ उपेक्षित जनों ने विज्ञापननुमा बयान दिये हैं कि वे ठीकरे फुड़वाने के लिए अपना सिर प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ठीकरों की तुलना में उनके सिर बहुत छोटे हैं। अगर फोड़ने की कोशिश की गई तो सिर के मुआवजे उपर से गले पड़ जाएगें। फिर इसमें त्याग और बलिदान की बू आ रही है। वे जानते हैं कि इस वक्त कोई ठीकरे फुड़वा लेगा तो कल उसके गले में उन्हें खुद माला डालना पड़ेगी, इज्जत का एक आसन देना पड़ेगा, बावजूद इसके क्या गैरंटी कि कल वंश परंपरा के दावों को भी वह स्वीकार कर लेगा।

कहने को पार्टी में जगह जगह हार के कारणों पर चिंतन बैठक चल रही है। किन्तु वास्तव में उनकी चिंता उपयुक्त सिर की तलाश है। बच्चों को जोखिम में नहीं डाल सकते, उन्होंने तो अभी अभी सिर उठाना सीखा है। अभी तो उन्हें ठीकरों का मतलब भी मालूम नहीं है। यह भी नहीं पता कि वे फूटते कैसे हैं। पता चलेगा तो शायद वे राजनीति से दूर ही रहना

चाहें। अगर कहीं ऐसा हो गया तो भी दिक्कत होगी।

पार्टी जिन्हें अपना चाणक्य कहती आई है, उन्हें बुलाया गया। पूछा कि - 'आप ही रास्ता बताइये .... कि ठीकरे भी फूट जाएं और शीर्षस्थ सिर भी बच जाएं।'

बहुत विचार के बाद वे बोले - 'हमें इतिहास में से कोई सिर ढूंढ़ना चाहिए। हमारा इतिहास महत्वपूर्ण सिरों से भरा पड़ा है। ठीकरों की तुलना में ये सिर बड़े भी हैं। समय समय पर हमने उन्हें श्रेय दिया है, उनके माथे पर पगड़ी बांधी है, गले में माला पहनाई है। आज समय आया है कि वे बुरे वक्त में पार्टी के काम आएं।'

''' ये नहीं हो सकता। इतिहास में तो वंश है।' उचित व्यक्ति ने आपत्ती की।

'' 'वंश के अलावा भी हैं इतिहास में ।'

'''वो पार्टी का इतिहास नहीं है। बाकी किसी को हम इतिहास नहीं मानते। आप कोई और रास्ता बताइये।'

'' 'मीडिया के सिर फोड़ दीजिए।' चाणक्य बोले।

' 'दुकान बंद नहीं कर रहे हैं हम।' उचित व्यक्ति ने नाराजी से कहा।

'फिर तो एक ही तरकीब है, जनता के सिर फोड़ दो। आम आदमी हर समय काम आते हैं।'

''ठीक, आम आदमी का सिर सही रहेगा। एक पत्थर से दो

शिकार। ....'

सहिष्णु समाज में पहचान की राजनीति के मायने

चित्रा माली

लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं

ओरियंटलिज्म एडवर्ड सईद की एक अत्यंत महत्वपूर्ण किताब है,जो 1978 में प्रकाशित हुई थी । इसमें पश्चिम के लोग पूर्व को किस तरह से देखते है,समझते हैं,उसका अध्ययन किया गया है, खासकर इस्लामिक देशों और वहां की धारणाओं को लेकर काफी चिंतन किया गया है । सईद कहते है कि पश्चिमी जगत में प्राच्य जगत की ये छवियाँ एक 'अन्य' की अवधारणा को रचती है,एक ऐसा 'अन्य' (Other) जो पश्चिम से अलग है,इसीलिए पश्चिम के लिए वह अजूबा है। 'प्राच्यवाद' की इस अवधारणा के द्वारा 'पश्चिम', पूरब की सभ्यताओं, भाषाओं, संस्कृतियों और ज्ञान परंपराओं से एक खास तरह से पेश आता है । वह 'पूरब' को अपने से अलग कर देता है । 'पश्चिम' अपनी सभ्यता, संस्कृति, भाषा,और ज्ञान परंपरा को श्रेष्ठ मानता है और इसी क्रम में वह एक 'अन्य' का निर्माण करता है जो उससे निम्न है जो पश्चिम को देखकर सभ्य सुसंस्कृत हो रहा है । जैसे ही 'अन्य' की बात होती है वहीं से 'अस्मिता (पहचान) विमर्श' प्रारंभ हो जाता है,अस्मिता विमर्श में अपनी अस्मिता को बनाए रखने के लिए 'अन्य' का निर्माण किया जाता है और उसकी तुलना की जाती है अपनी संस्कृति, सभ्यता और ज्ञान से,जब वह 'अन्य' को गढ़ रहा होता है,तो इस क्रम में विभेदक मानसिकता जन्म लेती है,जो समतामूलक समाज, धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक मूल्यों के लिए खतरनाक है । 'प्राच्यवाद' यह एक पश्चिम की दृष्टि है 'पूरब' को देखने की,वह इसी दृष्टि से वहां के वासियों का भी अध्ययन करता है । यह बात हुई 'प्राच्यवाद' की, लेकिन ऐसी ही विभेदक दृष्टि हम हमारे समाज में भी देखते है,जो हमें विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों और वर्गों में विभाजित करती है और एक अलगाव या पृथकता के सिद्धांत को विकसित करती है। जिसमें हर व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ और अन्य को 'हीन' समझता है । धर्म,जाति,और लिंग के आधार पर हमारा सामान्य व्यवहार भी परिवर्तित हो जाता है। इसी भेदभाव के आधार पर हिंसा के उग्र रूप हमारे सामने आते है । हर रोज हम अखबारों और सोशल मीडिया पर कोई न कोई अमानवीय व्यवहार की घटना जो एक खास वर्ग के साथ लगातार किसी न किसी रूप में की जा रही है,उनकी खबरें पढ़ते,देखते और सुनते रहते हैं । अभी हाल ही में एक फरमान जारी किया गया था जिसमें 'कावड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाली खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगी होनी चाहिए और रेस्टोरेंट मालिक अपना तथा अपने कर्मचारियों का नाम,धर्म और जाति सहित संपूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराए। इस फरमान के पीछे खाने की शुद्धता (शाकाहारी) व स्वच्छता का तर्क दिया गया था । इस फरमान के विरुद्ध तीन याचिका दायर की गईं थीं । पहली याचिका एसोसिएशन फ़ॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (एपीसीआर) दूसरी याचिका टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा और तीसरी याचिका प्रोफेसर अपूर्वानंद और आकार पटेल के द्वारा की गई थी । तीनों याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई की गई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 22 जुलाई 2024 को न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय व न्यायमूर्ति एस.वी.एन.भट्टी की पीठ ने अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसमें नेम प्लेट लगाने के आदेश पर रोक लगा दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी को भी जबरन नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। साथ ही इस फरमान पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार से जवाब भी मांगा गया है। यह निर्णय देश के संविधान और धर्मनिरपेक्ष राज्य के बने रहने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह फरमान सामान्य नहीं लग सकता है, यह हमारे अवचेतन मन की हिंसा और घृणा को प्रकट करता है चाहे वह किसी भी राज्य या व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा हो। एक खास तबके के साथ हमारा व्यवहार कुछ वर्षों से और अधिक खराब होता जा रहा है, न जाने कौन सा भय हमसे यह सब करवा रहा है। क्योंकि व्यक्ति जब डरा हुआ होता है तो वह अधिक हिंसक हो जाता है और तरह तरह के भेदों को उत्पन्न करता है। इस तरह के भेदभाव की घटनाएं लगभग सभी राज्यों में घटित हो रही है,कुछ वर्ष पूर्व एक व्यक्ति के रसोई घर में जाकर लोग फ्रिज चेक करते हैं और उसे मार डालते हैं और यह सब भीड़ एक खास तबके के खिलाफ कर रही होती है जिसका उसे कोई मलाल भी नहीं होता है। मध्यप्रदेश में भी ऐसी ही घटना घटित हुई थी,जिसमें मस्जिद के सामने बैंड बाजे बजाये गए और ऐसे नारे लगाए गए जिससे भय का माहौल उत्पन्न हो। बस ये महज इसलिए कि वह दूसरे धर्म के अनुयायी है। इस आधार पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। 1947 के विभाजन की त्रासदी दोनों मजहब के लोगों ने बराबरी से झेली है,उन घावों को भरने में काफी समय भी लगा है,इस तरह की घटनाएं

लगातार उन जख्मों को याद दिलाने का काम करती है। अलग अलग दल अस्मिताओं को उभारते हैं और इनका इस्तेमाल अपने पक्ष में करते हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार से अंग्रेजों ने किया था। हर सामान्य व्यक्ति इन अस्मिताओं में अपने आप को सुरक्षित समझता है और वह 'अन्य' के प्रति असहिष्णु होता जाता है । सोशल मीडिया के जरिए इस तरह के वीडियो का प्रचार प्रसार किया जाता है जिससे लोगों की मानसिकता को लगातार कुंठित कर हिंसा करने के लिए प्रेरित किया जा सके । सांप्रदायिक हिंसा की इन घटनाओं और हिंदू मुस्लिम अलगाव को देखकर ही गांधी जी ने 1922 में ही 'शांति सेना' का निर्माण करने का निर्णय लिया था,साथ ही गांधी जी ने अपने 18 रचनात्मक कार्यक्रमों में सांप्रदायिक सद्भाव को सबसे पहले रखा था। 1947 के विभाजन के बाद हो रहे सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए गांधी जी ने पंजाब, कलकत्ता, नोआखाली और बिहार की यात्राएं कीं जिससे तनाव को कम किया जा सके और सौहार्द का माहौल तैयार किया जा सके। गांधी इसमें सफल भी हुए लेकिन कुछ विरोधियों के द्वारा उस समय,उनकी राह में कांटे, कंकड़, शीशे के टुकड़े और गंदगी तक बिछाई गयी जिन्हें गांधी ने ताड़ के बढ़े पत्ते से बुहारते हुए आगे का मार्ग तय किया,बिना किसी शिकायत के 'एकला चलो रे' को गुनगुनाते हुए । गांधी जी कहते है 'मेरी यह लालसा है कि यदि आवश्यक हो तो मैं आपने रक्त से हिंदू और मुसलमानों के बीच संबंधों को दृढ़ कर सकूं।' हिंदू मुस्लिम एकता का अर्थ यह है कि हमारा समान प्रयोजन हो,समान ध्येय हो और समान गम हों । हम एक दूसरे के गमों में साझा होकर और परस्पर सहिष्णुता की भावना रखकर एक-दूसरे के साथ सहयोग करते हुए अपने सामान्य लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो यह हिंदू मुस्लिम एकता की दशा में सबसे मजबूत कदम होगा । हिंदू-मुस्लिम एकता का अर्थ केवल हिंदू मुसलमानों के बीच एकता नहीं है, बल्कि उन सब लोगों के बीच एकता है जो भारत को अपना देश समझते हैं, उनका धर्म चाहे जो हो । वैश्विक शांति, समतामूलक समाज, शांतिपूर्ण समाज की दृष्टि को विकसित करने का प्रयत्न गांधी जी के द्वारा लगातार किया गया। जो विभेदकारी दृष्टि (ओरियंटलिज्म) और भारतीयों द्वारा ही भारतीयों को अलग अलग धर्म,संप्रदाय, जातियों,नस्लों,वर्गों में विभाजत कर देखने की दृष्टि (ऑक्सिडेंटलिस्म) है जिसमें वे एक दूसरे को पृथकता से देखते और समझते हैं। खासकर हम और वे या कहें 'अन्य' की आवश्यकता को समाप्त करने का प्रयास गांधी जी के द्वारा किया गया। जिसमें कई अलग अलग अस्मिताओं को संतुलित करने का काम भी गांधी जी के द्वारा किया गया। इस दृष्टि को विकसित करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि मानव को सिर्फ मानव समझा जाए उसे धर्म,संप्रदाय, जातियों, वर्गों, नस्लों से परे रख एक माना जाए। जो सिर्फ अलग अलग रंगों के अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले अलग अलग धर्मों को मानने वाली एक इकाई है। जो हमारी विविधता में एकता का प्रमाण है। इस साझी संस्कृति और विरासत को बचाए और बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए जमीनी हकीकत से रूबरू होना आवश्यक है,जो परस्पर सहयोग सहिष्णुता ओर प्रेम के सार्वभौमिक नियम से संचालित होती है। इस तरह की विभेदक दृष्टि सामान्य जीवन में लोगों के पास नहीं है इसका निर्माण कुछ लोगों के द्वारा अपने हित के लिए किया जाता है उसे पहचाना जाना आवश्यक है। यह एक कदम होगा शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण समाज की ओर,जिसकी कल्पना गांधी जी ने की थी और आज भी कई अमन पसंद लोगों के द्वारा समाज में शांति संस्कृति को विकसित करने की कोशिशें लगातार जारी है,जिसमें विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से हिंसा और अहिंसा की समझ को विमर्शों के जरिए समझाने का प्रयास किया जा रहा है,साथ ही फिल्मों,नाटकों और कला के विभिन्न साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

नींव पुख्ता करने का बजट

बजट प्रतिक्रिया

प्रमोद भार्गव

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

इस आम बजट की तीन खास बातें हैं, जो रोजगार से लेकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली साबित हो सकती हैं। एक कृषि, दो रोजगार और तीन आयकर दाताओं को राहत। इसीलिए इस बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत काल के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानते हुए कहा है कि 'यह आम बजट पांच साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2029 तक विकसित भारत की आधारशिला रखने में अहम भूमिका निभाता रहेगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने खेती में उत्पादकता, बेरोजगारों को नामी कंपनियों में प्रषिक्षण देते हुए पांच हजार रुपए की परिश्रमिक राशि कि आर्थिक सहायता और बाजार को बढ़ावा देने की दृश्टि से कर सारणी में करप्रदाताओं को राहत। इसके अलावा समग्र मानव संसाधन विकास, ऊर्जा सुरक्षा, ढांचागत विकास, शोध-अनुसंधान जैसे विषयों को प्राथमिकता देते हुए बजट प्रावधान किया गया है।

युवाओं को रोजगार देश में इस समय एक बड़ी समस्या के रूप में देखी जा रही है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में दक्ष होने के बावजूद रोजगार दूर की कौड़ी बना हुआ है। इस समस्या के समाधान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पहल करते हुए रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी पांच योजनाओं के लिए दो लाख करोड़ रुपए का बजट तय किया है। पांच वर्षों में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं के लिए दक्षता प्राप्त करने हेतु 500 स्थापित कंपनियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन युवकों को केंद्र सरकार पांच हजार रुपए प्रतिमाह सीधे खाते में जमा कराएगी।

इस बजट में किसान और कृषि की स्थिति को मजबूत बनाने के नजरिए से 1.52 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। पिछले वर्ष इस मद में 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। अतएव अब 25000 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए गए हैं। पांच राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। हालांकि किसानों को फसल पर दी जाने वाली सब्सिडी पर इस बजट में कोई नया प्रावधान नहीं है। किसान एमएसपी के लिए अर्से से कानूनी रूप देने की मांग कर रहे हैं। यदि इसे कानूनी रूप दे दिया जाता है तो करीब 17 लाख करोड़ रुपए वार्षिक अतिरिक्त खर्च आएगा, नतीजतन देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। किसान उन्हीं फसलों को उगाएंगे, जिन पर ज्यादा सब्सिडी मिलेगी और जिनकी बाजार में मांग ज्यादा होगी। ऐसे में मोटे अनाज, जिनमें पोशक तत्व अधिक होते हैं, उन्हें किसान खेतों में नहीं बोएंगे। जबकि बीमार होते देश के लिए मोटे अनाज आज की जरूरत बन गई है।

इस बजट में आम करदाता को खुश रखने की कोशिश की गई है, इसलिए कर सारणी में सुधार किया गया है। अब तीन लाख की आमदनी पर कोई कर नहीं लगेगा। तीन से सात लाख रुपए की आय पर पांच फीसदी, सात से दस लाख पर 10 फीसदी, दस से बारह लाख पर 15 फीसदी, बारह से पन्द्रह लाख पर 20 फीसदी और पन्द्रह लाख से अधिक आय पर 30 प्रतिशत कर लगेगा। जो कि करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत है। इससे बाजार में पैसे की तरलता बढ़ेगी और व्यापारियों को आर्थिक लाभ होगा।

बजट में कैंसर की दवा, सोना-चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चॉर्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सौर ऊर्जा संयंत्र, चमड़ा और समुद्री खाद्य साम्रगी सस्ते होंगे। सौर घर योजना पर सब्सिडी जारी रहेगी। मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है। सोना और चांदी के गहनों पर भी यह ड्यूटी घटाकर 6 प्रतिशत कर दी गई है। संचार, उपकरण 15 प्रतिशत और प्लास्टिक का समान 25 प्रतिशत महंगे किए गए हैं। यह साम्रगी इसलिए महंगी की गई है, क्योंकि यह साम्रगी खराब होने के बाद फेंक दी जाती है, जिससे हर तरह का प्रदूषण बढ़ता है। साथ ही पशुधन के मुंह में भी यह साम्रगी चली जाती है, जिससे जानवर बेमौत मारे जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार नीतिश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैशाखियों पर टिकी है। अतएव इन दोनों नेताओं की मांग पूरी करते हुए बिहार को 59 हजार करोड़ रुपए और आंध्रप्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया गया है। लिहाजा माना जा रहा है कि पूरी पांच साल राजग गठबंधन सरकार केंद्रीय सत्ता में बनी रहेगी।

अनुचित है, सरकारी कर्मचारियों की संघीय भागीदारी

विगत दिनों सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर 58 साल से लगा हुआ प्रतिबंध इस सरकार ने हटा लिया है। यह केन्द्र सरकार के संपूर्ण भगवाकरण पर लगी हुई फिलहाल एक मात्र औपचारिक रोक ही बची थी जिसे हटाकर हटा कर वर्तमान सरकार संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ कर रही है हालांकि जैसा कि विगत दस वर्षों में हमने भली-भांति इस बात को समझ लिया है कि भाजपा सरकार संघ का ही एक अनुषंगी संगठन जिसमें संगठन से लेकर पीएम, लोकसभाध्यक्ष वगैरह वगैरह शाखाओं की उपज हैं। इसी विचारधारा से जुड़े लोग बड़ी तादाद में प्रशासन और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में पदस्थ हैं। न्याय पालिका में भी संघ की गहरी पैठ बनी हुई है।

मुद्दा

सुसंस्कृति परिहार

लेखक स्तंभकार हैं।

लौह पुरुष सरदार बल्लभभाई पटेल ने 21 अप्रैल 1947 को दिल्ली के मैटकाफ़ हाउस में अखिल भारतीय सिविल सेवा का उद्घाटन करते हुए इसे 'स्टील फ्रेम ऑफ़ इंडिया' कहा था। यानी सिविल सेवा से एक ऐसे इस्पाती ढाँचे के रूप में काम करने की अपेक्षा की गयी थी जिसकी एकमात्र प्रतिबद्धता संविधान और क़ानून का शासन हो। इसके लिए जाति या धर्म की संकीर्णताओं से मुक्त रहना लाज़िमी था। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को राजनीति से दूर रहना था ताकि सरकारों के आने-जाने से इस ढाँचे पर कोई फ़र्क़ न पड़े।

विदित हो,देश में जारी तमाम उथल-पुथल के बीच 1966 में सरकारी कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमाते इस्लामी की गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगायी गयी थी। डिप्टी सेक्रेटरी आर.एम.श्रॉफ़ के हस्ताक्षर से जारी ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया था कि इन दोनों संगठनों की गतिविधियों में भाग लेने से सिविल सेवा आचरण नियमावली, 1964 के नियम-पाँच का उल्लंघन होता है जो राजनीति में भागीदारी करने से सरकारी कर्मचारियों को रोकता है।

विगत दिनों सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर 58 साल से लगा हुआ प्रतिबंध इस सरकार ने हटा लिया है। यह केन्द्र सरकार के संपूर्ण भगवाकरण पर लगी हुई फिलहाल एक मात्र औपचारिक रोक ही बची थी जिसे हटाकर हटा कर वर्तमान सरकार संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ कर रही है हालांकि जैसा कि विगत दस वर्षों में हमने भली-भांति इस बात को समझ लिया है कि भाजपा सरकार संघ का ही एक अनुषंगी संगठन जिसमें संगठन से लेकर पीएम, लोकसभाध्यक्ष वगैरह वगैरह शाखाओं की उपज हैं। इसी विचारधारा से जुड़े लोग बड़ी तादाद में प्रशासन और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में पदस्थ हैं। न्याय पालिका में भी संघ की गहरी पैठ बनी हुई है। यह मायनेखेज है कि शाखा वालों ने अपनी पहुंच हर जगह बना रखी है।

तब देश के करोड़ों कर्मचारी क्यों ना खुलकर संघ की शाखाओं और उनके प्रवचन कार्यक्रमों में जाएं। कोई पर्देदारी ना रहे। संघ के एक आव्हान पर वे जहां बुलाएं उपस्थित रहें। आगे आप समझदार हैं जिसने आनाकानी की उसकी खैर नहीं। अब सरकारी कर्मचारी तो स्वभावतः सत्तारुढ़ सरकार के गुलाम ही माने जाते रहे हैं लेकिन उनका वोट निष्पक्ष रहता आया है कोई ज़ोर जबरदस्ती नहीं हुई। पिछले तमाम चुनावों में ऐसा ही होता रहा है। किंतु विगत सालों में बढ़ती मंहगाई तथा शासन के अनधिकृत हस्तक्षेप से कर्मचारियों का रुख़ बदला है यह उनके डाक मतपत्रों से उजागर हुआ है जिस पर संघ की नज़र है वे चाहते हैं कि कर्मचारियों की वोट संघ/भाजपा को ही मिले। इसलिए उन्हें अपने से जोड़कर डराने और दबाने के लिए यह छूट दी जा रही है। वे इन्हें सत्ता के गुलाम समझते हैं और यह भी भली-भांति जानते हैं कि इनसे अच्छा सस्ता कार्यकर्ता नहीं मिल सकता। कर्मचारियों का वोट ईवीएम में मिक्स नहीं होता तथा मतदान केन्द्र की वोट का भी खुलासा हो जाता है इसलिए वे दबिश में भी रहते हैं। इस व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। जिसमें गोपनीयता नहीं रहती। मतदाता डरते हैं।

बहरहाल, अप्रत्यक्ष तौर पर देश में अप्रत्यक्ष तौर पर संघ का ही साम्राज्य कायम है। ये बात और कि अब गुजरात के अवतारी पुरुष अपने गुरु के साथ ताल ठोकने में लगे हैं गुरु पूर्णिमा पर गुरु को खुश करने के लिए ही भाजपा सरकार ने कर्मचारियों के लिए यह द्वार खोल दिए हैं जो सिर्फ तथाकथित भाजपा के प्रिय सरदार बल्लभभाई पटेल की ही उपेक्षा नहीं है बल्कि संविधान की मनोभावना की घोर उपेक्षा है। कर्मचारी जो अब तक अपना शासकीय दायित्व मनोयोग से निभा रहा था लेकिन मत मनमर्जी से देता रहा उसे संघ का गुलाम बनने मज़बूर किया जाएगा तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का अवसान सुनिश्चित है। समय रहते इस बदले कानून पर सुको को संज्ञान लेना चाहिए।

गांजा बेचते युवक को किया गिरफ्तार

बैतूल। कोतवाली पुलिस ने गांजा बेचते एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 22 जुलाई सोमवार को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रशांत ढाबे के पास एक युवक खड़ा है और गांजा बेचने के फिराक में है। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और मिली जानकारी के आधार पर सफेद टी-शर्ट में खड़ा युवक जिसके पास काले रंग का बैग था। उक्त युवक को पुलिस ने पकड़ा, जिसने अपना नाम अनिकेत पिता अरुण पाठक 20 वर्ष, निवासी अर्जुन नगर बैतूल होना बताया गया। उक्त युवक के बैग की तलाशी ली गई तो उसके पास 4.074 किलोग्राम गांजा प्राप्त हुआ है। जब्त किए गए गांजे की कीमत 18 हजार रुपए बताई जा रही है। उक्त युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मामला दर्ज कर युवक को न्यायालय में पेश किया गया। युवक को गिरफ्तार करने में कोतवाली थाना के उपनिरीक्षक दिनेश कुमरे, उपनिरीक्षक नितीन उईके, सहायक उपनिरीक्षक जगदीश रैकवार व दिलदार सिंह, प्रधान आरक्षक कामता प्रसाद, आरक्षक नितिन, आरक्षक संजू, आरक्षक दिनेश उईके, आरक्षक सोनू रघुवंशी, विष्णु सिंह आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

डॉ. पिता के हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास की सजा

घटना के 4 वर्ष बाद न्यायालय ने सुनाई सजा

बैतूल। डॉक्टर पिता की हत्या करने वाले नाबालिग बेटे को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। डॉक्टर की 4 वर्ष पहले नकाबपोशों ने कुल्हाड़ी, फावड़े और अन्य हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी थी। हत्या की घटना का खुलासा मिले उंगलियों के निशान से हुआ है। जानकारी के मुताबिक चोपना थाना क्षेत्र के ग्राम विष्णुपुर में एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी और बेटे ने बताया था कि अज्ञात नकाबपोशों ने हमला कर हत्या कर दी है। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम ने फिंगरप्रिंट लिए गए। मौके से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए। इस साक्ष्य के आधार पर हत्या की घटना का खुलासा किया गया। हत्या के बाद फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ आबिद अहमद अंसारी ने मौके से फिंगरप्रिंट लिए थे। जिसके मिलान के लिए थाना प्रभारी चोपना से संदेहियों और परिजनों के फिंगरप्रिंट मांगे गए। जब इनका मिलान किया तो हत्या में उपयोग हुए औजारों पर 17 वर्ष के नाबालिग बेटे की उंगलियों के निशान मिले है। इसके बाद सख्ती से पूछताछ की गई। मां-बेटे ने जुर्म कबूल कर पूरा घटनाक्रम बयां कर दिया। इसी आधार पर कोर्ट ने भी आरोपी बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई। जबकि साक्ष्य नहीं मिलने पर महिला को बरी कर दिया।

पत्नी ने पुलिस को घटना के संबंध में दी थी यह जानकारी...- मृतक की पत्नी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि पति मुझे और बच्चों को छोटी-छोटी बातों पर आए दिन पीटते थे। घटना के एक दिन पहले भी उन्होंने मुझे आवाज दी। सुन नहीं पाई तो मारपीट की। इसके बाद मैंने पति को जान से मारने का ठान लिया था। 1 जून 2020 को जब बच्चे और पति खाना खाकर सो गए, तो मैं दूसरे कमरे में रखी गैती, कुल्हाड़ी और वसूला ले आई। सबसे पहले गैती से पति पर हमला किया। वे नींद में थे, हमले से चीख उठे। आवाज सुनकर बड़ा बेटा जाग गया। मेरे कहने पर उसने बगल में रखी कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर दिया। इस बीच बेटी वहां पहुंच गई। उसने पिता को मारने का विरोध किया और बचाने की कोशिश करने लगी। जिसमें वह भी घायल हो गई।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शाहपुर में रिक्त सीटों पर प्रवेश की अंतिम तिथि 26 जुलाई

बैतूल। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शाहपुर में कक्षा-11वीं में रिक्त सीटों पर 26 जुलाई 2024 तक प्रवेश दिया जाएगा। प्राचार्य श्री पंकज शर्मा ने बताया कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शाहपुर में कक्षा-11वीं में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए अनुसूचित जनजाति के बालक एवं बालिका कार्यालयीन समय 11 बजे से 3 बजे के मध्य आवेदन कर सकते है। उन्होंने बताया कि प्रवेश के लिए पिछली कक्षा का परीक्षा-फल न्यूनतम 60 प्रतिशत होना अनिवार्य है। छात्र-छात्राओं का एमपीटास पर प्रोफाइल पंजीयन होना अनिवार्य है तथा प्रवेश की समस्त प्रक्रिया एमपीएसआरएस द्वारा जारी प्रवेश मापदंडों के अनुसार की जाएगी। सीबीएसई के छात्र-छात्राओं को प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए विद्यार्थी को पिछली कक्षा की अंकसूची, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, एमपी टॉस पर प्रोफाइल पंजीयन, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड दस्तावेज अनिवार्य है।

कार एवं मोटरसाइकिल दुर्घटना में तीन की मौत दो घायल

ग्राम शिरडी एवं दुनावा में दर्दनाक दुर्घटना

बैतूल/मुलताई। मुलताई क्षेत्र के ग्राम शिरडी एवं दुनावा मे हुई दो अलग-अलग दुर्घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि दो लोग घायल हो गए। शिरडी में बोलोरो कार दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया वहीं दुनावा के पास हुई मोटरसाइकिल दुर्घटना में एक वृद्ध की मौत हो गई और एक घायल हो गया। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार मासोद आठनेर रोड पर बीती रात एक भीषण सड़क हादसा सामने आया। शिरडी के पास एक बुलेरों अचानक से अनियंत्रित हो गई और दूर जा फिकाई। इस हादसे में बुलैरो वाहन के परखच्चे उड़ गए जबकि बुलेरो में सवार दो युवकों की मौके पर मौत हो गई जबकि एक युवक घायल बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार 24 वर्षीय सांवरी निवासी अतुल शिवराम बुआडे अपने दोस्त आकाश माथनकर के साथ आठनेर से मासोद बुलेरो से जा रहा था। उनके साथ बैतूल निवासी एक अन्य युवक भी था। अचानक से शिरडी के पास उनका वाहन अनियंत्रित हो गया और पलटी खाते हुए दूर जा फिकाया। हादसे के बाद अतुल और आकाश की मौके पर ही मौत हो गई जबकि बैतूल निवासी युवक घायल बताया जा रहा है। सांवरी और बांड्या बघौली निवासी युवकों की मौत के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है।

बुजुर्ग को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, एक की मौत, एक घायल

मुलताई। पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम दुनावा में एक बाइक चालक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं उसके साथ बाइक पर सवार एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। दोनो को तत्काल मुलताई के सरकारी अस्पताल लाया गया। जहा डॉक्टर द्वारा बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं दूसरे व्यक्ति का उपचार किया गया। बताया जा रहा है की काठी निवासी बाबू बुआड़े उम्र 55 वर्ष बाइक से अपने घर की ओर काठी जा रहे थे। तभी एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी और मौके से भाग गया। टक्कर के चलते बाबू की मौके पर मौत हो गई। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले में जांच की जा रही है। मुलताई अस्पताल में मृतक बुजुर्ग के शव का पोस्टमार्टम करवा कर उसके परिजनों को सौप दिया गया है।

केंद्रीय मंत्री के प्रयासों से जिले को मिली बड़ी सौगात

198.02 करोड़ की 11 सिंचाई परियोजनाओं की मंजूरी

बैतूल। केन्द्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने जिले में सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए मप्र शासन के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव एवं सिंचाई मंत्री तुलसी सिलावट से मुलाकात कर 198.02 रूपये की 11 जल परियोजनाओं को बैतूल जिले के लिए स्वीकृति दिलाई है। इन 11 परियोजनाओं को स्वीकृति मिलने से जिले में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। श्री उइके के विशेष प्रयासों का ही परिणाम है कि किसानों के हित में सिंचाई के क्षेत्र में 198.02 करोड़ की सौगात जिले को मिली है।

सीएम और जल संसाधन मंत्री से की थी मांग

गौरतलब है कि विगत कई वर्षों से जिले की जनता द्वारा विभिन्न जल परियोजनाओं की मांग की जा रही थी, अपने क्षेत्र की जनता की आवाज को श्री उइके ने पुरजोर तरीके से उठाकर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एवं जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को इन मांगों से अवगत कराया था। अब मध्यप्रदेश शासन के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट द्वारा जल संसाधन विभाग के वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु सिंचाई के रकबे को बढ़ाने के उद्देश्य से 198.02 करोड़ की लागत से बनने वाली 11 जल परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए उइके ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव एवं जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का आभार व्यक्त किया है।

5444 हेक्टेयर बढ़ेगा सिंचाई रकबा

केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि वह मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री से

भेंट कर इन जल परियोजनाओं को स्वीकृत कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे। अब उनके प्रयासों से बैतूल जिले को 198.02 करोड़ की लागत से बनने वाली 11 जल परियोजनाओं की स्वीकृति इस वार्षिक बजट में मिली है जिससे 5444 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा।

केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि जिन 11 परियोजनाओं को जल संसाधन मंत्री द्वारा स्वीकृत किया है, इससे किसानों को पर्याप्त पानी मिलेगा। उनकी फसल खेतों में लहलहाएगी। हमारा जिला कृषि प्रधान है, इसलिए यह परियोजनाएं किसानों के लिए लाभदायक होगी। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान संसदीय क्षेत्र को अधिक से अधिक सौगात दिलाना उनका प्रयास है। लोगों की मांग के आधार पर तय किया जाएगा कि जहां जरूरत महसूस हो, उन कामों को स्वीकृत कराया जाए। उन्होंने बताया कि हर क्षेत्र में सौगात दिलाने के लिए उनका प्रयास रहेगा।

11 जल परियोजना से बढ़ेगा सिंचाई का रकबा

केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री उइके ने बताया कि 116.00 करोड़ की लागत की रामघाटी सिंचाई परियोजना से 3000 हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, 5.42 करोड़ की लागत की कोयलारी टैंक (नहर रहित) परियोजना से 193 हेक्ट. क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, 8.34 करोड़ की लागत की मजरीघोघरा टैंक (नहर रहित) परियोजना से 299 हेक्ट. में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, 9.53 करोड़ की लागत की पारेगांव परियोजना से 280 हेक्ट. में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, 5.71 करोड़ की लागत की जामगांव परियोजना से 170 हेक्ट. में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, 14.98 करोड़ की लागत की राखीढाना परियोजना से 400 हेक्टर. में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, 5.81 करोड़ की लागत की जाम परियोजना से 159 हेक्ट. में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, 10.69 करोड़ की भैसादंड परियोजना से 314 हेक्ट. में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, 5.72 करोड़ की देवरी परियोजना से 165 हेक्ट. में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, 10.14 करोड़ की खुसरंगढाना परियोजना से 298 हेक्ट. में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा तथा 5.68 करोड़ की चिल्हाटी परियोजना से 175 हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा।

करोड़ों रुपये की लागत से बनाई जाने वाली इन परियोजनाओं का फायदा जिले के हजारों किसानों को होगा, जिन किसानों के खेतों में पानी की कमी की वजह से फसलें नहीं हो पाती थी अब उन किसानों के खेतों में भी लहलहाती फसलें जहां देखने को मिलेगी तो वहीं किसान आर्थिक रूप से सम्पन्न भी हो सकेंगे।

विधायक के प्रयासों से मजरे घोघरा डैम स्वीकृत

बजट में 8 करोड़ 34 लाख रुपये की मिली स्वीकृति, 290 हेक्टेयर क्षेत्र में होगी सिंचाई

बैतूल। विधानसभा क्षेत्र बैतूल के विधायक हेमंत खंडेलवाल के विशेष प्रयासों से आठनेर विकासखण्ड में मजरेघोघरा जलाशय स्वीकृत हो गया है। 2024-25 के वार्षिक बजट में मजरे घोघरा टैंक निर्माण के लिए 8 करोड़ 34 लाख रुपये की स्वीकृत मिली है। मध्यम सिंचाई योजना के मजरे घोघरा जलाशय से 290 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि बैतूल विधायक हेमंत खण्डेलवाल द्वारा जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट से असिंचित क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधा के लिए मजरेघोघरा जलाशय स्वीकृत करनें की मॉग की गई थी। मॉग को गंभीरता से लेकर जल संसाधन मंत्री द्वारा उक्त जलाशय निर्माण की स्वीकृत देकर जलाशय निर्माण के लिए वार्षिक बजट में 8.34 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

किसानों की वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी-

उल्लेखनीय है कि पहाड़ी क्षेत्र में स्थित मजरेघोघरा ग्राम के आसपास सिंचाई सुविधाए नहीं होनें से यहा के किसान सिर्फ बारिश में एक ही फसल खरीफ की खेती करते थे। यहा के किसानों द्वारा वर्षो से सिंचाई सुविधा के लिए डेम निर्माण की मॉग की जा रही थी। किसानों को सिंचाई सुविधा की सौगात देनें के लिए बैतूल विधायक द्वारा म.प्र के जल संसाधन मंत्री से मुलाकात कर मजरे घोघरा जलाशय की स्वीकृत के लिए सतत प्रयास किये गये। बैतूल विधायक के प्रयासों से मजरेघोघरा ग्राम सहित आसपास के किसानों की वर्षों पूर्व से की जा रही डेम स्वीकृत करानें की मांग पूरी हो गई। मजरेघोघरा ग्राम के समीप स्थानीय नदी पर 8 करोड़ 34 लाख रुपये की लागत से बनने वाल जलाशय से लगभग देढ़ सौ किसानों को 290 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी।

जनसुनवाई में पिता की गुहार पर कलेक्टर ने तुरंत सहायक आयुक्त को भेजकर बेटियों को दिलवाई टीसी

बैतूल। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी को जनसुनवाई के दौरान शाहपुर तहसील के मोतीदाना निवासी परमा ठाकुर ने आवेदन दिया कि शाहपुर तहसील में संचालित गुड शेफर्ड स्कूल द्वारा उनकी बेटी परी ठाकुर और पलक ठाकुर को टीसी नहीं दी जा रही है। पुत्री पलक कक्षा 8वीं एवं परी कक्षा 7वीं में अध्ययनरत है। आवेदन के माध्यम से बताया कि उनकी बेटी का चयन मॉडल स्कूल में हुआ है। टीसी जमा करने के लिए काफी कम समय बचा है, उन्हें स्कूल प्रबंधक द्वारा सातवीं और आठवीं की टीसी नहीं दी जा रही है। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने स्वयं अपनी कार से सहायक आयुक्त के साथ उन्हें शाहपुर के गुड शेफर्ड स्कूल भिजवाया। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी के हस्तक्षेप के बाद परी और पलक ठाकुर को स्कूल से तत्काल टीसी प्रदान की गई। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई ऐसे करें कि आवेदक को एक ही प्रकरण के लिए दोबारा जनसुनवाई में नहीं आना पड़े। श्री सूर्यवंशी मंगलवार को जनसुनवाई में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने 130 आवेदनों पर जनसुनवाई की। इस अवसर पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी ओमपाल भदौरिया, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

पीएम आवास योजना की अनुदान राशि प्रदान करने की मांग- मुलताई नगर के तिलक वार्ड निवासी सुशीला पति मंगल तायवाड़े ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली अनुदान राशि प्रदान किए जाने की मांग की। आवेदन के माध्यम से बताया कि मार्च 2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रकरण स्वीकृत हो चुका है, लेकिन आज दिनांक तक मिलने वाली राशि अप्राप्त है। उनका मकान जर्जर अवस्था में है एवं रहने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवेदिका ने बताया कि इस संबंध में नगर पालिका में पूछताछ करने पर कोई संतुष्टि पूर्ण जवाब नहीं दिया जाता है। आवेदिका ने प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि प्रदान किए जाने की मांग की, जिससे वह अपने मकान का काम शुरू कर सके। प्राप्त आवेदन पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने मुलताई नगर पालिका के संबंधित अधिकारियों को जांच कर निराकरण किए जाने के निर्देश प्रदान किए।

सड़क एवं नाली निर्माण की मांग- जनसुनवाई में चंद्रशेखर वार्ड निवासी बलिराम पंवार ने सड़क एवं नाली निर्माण किए जाने की गुहार लगाई। आवेदन के माध्यम से बताया कि वर्ष 1988 से चंद्रशेखर वार्ड में निवासरत है। वार्ड में सडक़ एवं नाली का निर्माण नहीं होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान समय में बारिश का पानी घरों में घुस जाता है और आवागमन में परेशानी होती है। प्राप्त आवेदन पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने नगर पालिका के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए।

पीपीओ, डीपीएफ की राशि देने की लगाई गुहार- भूतपूर्व शासकीय सेवक श्रीराम पात्रीकर ने सेवानिवृत्ति के लगभग 4 माह बाद किसी भी मद की राशि नहीं मिलने की शिकायत जनसुनवाई में की। आवेदन के माध्यम से बताया कि शाहपुर में पटवारी के पद पर पदस्थ थे। उन्हें 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त किया गया, परंतु चार माह बीत गए पीपीओ, ग्रेच्युटी, डीपीएफ की राशि आज दिनांक तक अप्राप्त है। आवेदन पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को जांच कर प्रकरण का निराकरण किए जाने के निर्देश प्रदान किए। बैतूल के ग्राम कोलगांव निवासी किसनलाल पांसे ने जनसुनवाई में आवेदन देकर किसी भी विभाग में भृत्य के पद पर रख नौकरी दिए जाने की मांग की। आवेदन के माध्यम से बताया कि वर्तमान में उन्हें नौकरी की आवश्यकता है। परिवार की जिम्मेदारी है। किसी भी बैंक से ऋण दिलवाया जाए, ताकि मैं कोई व्यवसाय कर सकूं या कोई भी विभाग में भृत्य का चौकीदार के पद पर रखा जाए। आवेदन पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए।

गुरुकुल कान्वेंट स्कूल ने विद्यार्थियों को टीसी देने से किया इंकार- ग्राम ताईखेड़ा स्थित गुरुकुल कान्वेंट स्कूल द्वारा तीन विद्यार्थियों को टीसी नहीं दिए जाने का मामला जनसुनवाई में पहुंचा। दरअसल ग्राम बद्योड़ा निवासी संजय पिता बाबाराव की बेटी दीक्षा और लावन्या तथा दिनेश दारोकर का पुत्र साई सिद्धी ग्राम ताई खेड़ा के गुरुकुल कान्वेंट स्कूल में अध्ययनरत थे। आवेदन के माध्यम से विद्यार्थियों के पिता दिनेश दारोकार एवं संजय ने बताया कि वे मजदूरी का कार्य करते है। स्कूल द्वारा बच्चों की फीस सरकार से लेने की बात कही थी, लेकिन स्कूल वेन और परीक्षा फीस उनके द्वारा दी गई। स्कूल की ओर से अधिक राशि की मांग की जा रही है। आवेदकों ने बताया कि वे मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते है। ऐसे में प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना संभव नहीं है। स्कूल प्रबंधन से बच्चों की टीसी दिए जाने की मांग की गई। परंतु स्कूल प्रबंधन ने टीसी विद्यार्थियों की टीसी देने से मना कर दिया गया। प्राप्त आवेदनों पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने संबंधित अधिकारियों को जांच के निर्देश प्रदान किए।

जनपद अधिकारियों ने सार्वजनिक कामथ कुंए को बताया उपयोगी

आर आई पटवारी ने बताया था अनुपयोगी, कामथ सार्वजनिक कुआं विवाद, ग्रामीणों में रोष

बैतूल/मुलताई। मुलताई नगर की सीमा से लगी ग्राम पंचायत कामथ में पंचायत द्वारा बनाया गए कुएं को बंद करने के प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीते दिनों नगर के एक व्यापारी ने ग्राम पंचायत कामथ के सार्वजनिक कुएं को अनुपयोगी बताते हुए इसे बंद किए जाने का आवेदन लगाया और रोचक तथ्य यह है कि मामले की जांच करने पहुंचे आर आई और पटवारी ने इस सार्वजनिक कुंए को अनुपयोगी बता दिया। जब इस बात की जानकारी खंड पंचायत अधिकारी, उपयंत्री सहित ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों को लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर कुएं के जल का ग्राम पंचायत के लिए उपयोग होने का पंचनामा बनाया। हालांकि अब अधिकारी यह कह रहे हैं कि सार्वजनिक कुए को बंद नहीं किया जाएगा किंतु बड़ा प्रश्न यह है कि एक ओर शासन जहां परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं बना रहा है। वही शासन के लाखों रुपए की लागत से बने कामथ ग्राम पंचायत के सार्वजनिक कुंए को सिर्फ एक आवेदन के आधार पर अनुपयोगी बता देना एक गंभीर मामला है। जिसमें आर आई , पटवारी की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे है।

बगैर रास्ते के खरीदी जमीन अब शासकीय कुए को करा रहे बंद- जनपद सदस्य सजना जीवन डोगर दिए एवं ग्राम पंचायत सरपंच पुष्पा जीतू डहारे बताती हैं कि कामथ ग्राम पंचायत की पेयजल समस्याओं को देखते हुए लगभग 6 लाख की लागत से 2016-17 में कामथ में शासकीय कुंए का निर्माण किया गया। लगभग आधे कामथ में इस कुएं से पेयजल

सप्लाई होती है। 2022 में नगर के एक व्यापारी महेश अग्रवाल ने इस कुएं से लगी बगैर रास्ते की भूमि को खरीदा और 2 वर्ष बाद मध्य प्रदेश शासन के एक मंत्री से इस कुएं को अनुपयोगी बताते हुए इसे बंद किए जाने की मांग की । शिकायत प्राप्त होने पर तहसीलदार ने आर आई और पटवारी को मामले की जांच के आदेश दिए आर आई पटवारी ने व्यापारी की शिकायत की पुष्टि करते हुए सार्वजनिक कुएं को अनुपयोगी बता दिया। जिसको लेकर कामथ ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि और नागरिकों में भारी रोष देखा गया । जनप्रतिनिधियों ने जनपद के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर बताया कि जीस कुएं के निर्माण में शासन की लाखों रुपए की राशी लगी हो जिस कुएं से आठ माह पेयजल आपूर्ति की जाती हो उसे बंद कैसे किया जा सकता है. इसके बाद उपयंत्री और जनपद अधिकारियों ने इसके उपयोगी होने का पंचनामा बनाया।

इनका कहना

जीस सार्वजनिक शासकीय कुएं में शासन की राशि लगी है उसे बंद नहीं किया जा सकता। मामला खत्म हो गया है।

- **अनामिका सिंह** तहसीलदार मुलताई

कॉलेज में पकड़ाया मुन्नाभाई, दूसरे छात्र की जगह दे रहा था परीक्षा, पहले भी दे चुका है चार पेपर

बैतूल/मुलताई। मुलताई नगर के शासकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय में भोज विश्वविद्यालय की ओर से संचालित बीए थर्ड ईयर एग्जाम के पांचवे पेपर में कॉलेज प्रशासन ने एक मुन्नाभाई को पकड़ा हैं। बताया जा रहा है कि नकल रोकने के लिए की जा रही जांच के दौरान शंका के आधार पर चेतन अमरुते नामक मुन्ना भाई को पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि यह मुन्ना भाई ऋतिक सिंह ठाकुर की जगह परीक्षा दे रहा था। पकड़े गए आरोपी ने ही पिछले चार पेपर भी ऋतिक बनकर दिया था। मामले में कॉलेज प्रशासन द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने कॉलेज आकर आरोपी को अपने साथ थाने ले गई। पूरे मामले में पकड़े गए आरोपी का कहना है कि पिछले चार पेपर भी उसी ने दिया था। आरोपी द्वारा बताया गया कि वो अपने दोस्त की जगह पेपर दे रहा था। इधर पुलिस द्वारा मामले में जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे की जांच भी की जा रही है।

बजट 2024 सही दिशा में एक अच्छा बजट है

सुनील हिरानी

बजट 2024 में आयकर अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जिसके तहत वे कर्मचारी जो वेतन भोगी है उनकी स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50000 से बढ़कर 75000 किया गया है तथा आयकर के स्लैब में जो परिवर्तन किया गया है उससे 17500 की बचत एक वेतन भोगी कर्मचारी को होगी। विगत कुछ महीनों से शेयर मार्केट में जो अनियमित उछाल आ रहा था उस पर लगाम लगाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैपिटल गेन टैक्स 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करना एक कड़ा कदम है जिसके दीर्घकालीन लाभ देश की गरीब जनता को मिलेंगे। देश के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने तथा बेरोजगारी पर लगाम कसने की दिशा में यह बजट है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 लाख करोड़ का बजट ग्राम विकास की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। संस्था कोई भी हो, परिवार अथवा देश बिना कोई बड़ा कदम उठाए सुधार असंभव है, आयकर में आलोचना की परवाह किए बिना जो कड़े कदम उठाए गए हैं वह मोदी सरकार के बस की ही बात है जिसके अच्छे परिणाम आगे दिखेंगे। यह एक संतुलित बजट है तथा इसकी दिशा विकसित अर्थव्यवस्था है क्योंकि समाज में संतुलन ही उसकी आधारशिला होती है जिस दिशा में यह बजट है। स्ट्रीट फूड भारत की पहचान है, अब देश में 100 ऐसे हब बनेंगे जहां पारंपरिक स्ट्रीट फूड का आनंद पूरी दुनिया के लोग लेंगे। बड़े शहरों में जल प्रबंधन एक बड़ी समस्या है जिसके लिए 100 बड़े शहरों में बड़ा कार्य होगा। 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 शहरों में पारगमन उन्मुख विकास परियोजना पर बड़ा खर्च होगा जिससे कि ट्रांजिट की समस्या से मुक्ति मिलेगी। यद्यपि राजकोषीय घाटा कम करने के लिए इस बजट में पर्याप्त कदम उठाए गए हैं परन्तु सरकार द्वारा कुछ अन्य उपायों पर विचार किया जा सकता था जैसे विनिवेश आदि। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाते आयकर के आमूल चूल परिवर्तन दशकों से अपेक्षित थे जिस दिशा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ठोस कदम बढ़ रहे हैं जिसका इंतजार देश को है। कुल जमा बात यह है कि दिशा यदि सही हो तो गति कम है या ज्यादा इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता।

राजस्थान जलसंकट

शारदा लुहार

खारे पानी की समस्या से जूझते ग्रामीण इलाके

देश के अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी मानसून प्रवेश कर चुका है. राज्य के कई ज़िलों में मानसूनी बारिश हो रही है. कहीं कहीं सामान्य से अधिक वर्षा हो चुकी है. राज्य मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार एक जून से 20 जुलाई तक पूरे राजस्थान में सामान्य से लगभग साढ़े तीन प्रतिशत अधिक बारिश हो चुकी है. यकीनन मानसून की यह बारिश राजस्थान के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है क्योंकि देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान सबसे अधिक गर्मी का प्रकोप झेलता है. इस दौरान राज्य में पानी की सबसे बड़ी समस्या उभर कर सामने आती है. विशेषकर राज्य के ग्रामीण क्षेत्र इससे बहुत अधिक प्रभावित होते हैं. राजस्थान के कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां लोगों को खारा पानी पीने पर मजबूर होना पड़ता है. एक तरफ प्रचंड गर्मी का कहर, तो दूसरी ओर खारा पानी उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है. न केवल इंसान बल्कि जानवर भी खारा पानी पीकर बीमार हो जाते हैं.

इस समस्या से जूझ रहे राज्य के कई ग्रामीण इलाकों की तरह करणीसर गांव भी इसका उदाहरण है. ब्लॉक मुख्यालय लूणकरणसर से करीब 35 किमी दूर इस गांव की आबादी लगभग साढ़े तीन हजार है. गांव की 35 वर्षीय शारदा देवी बताती हैं कि गर्मी के दिनों में गांव में सबसे बड़ी समस्या पानी की हो जाती है. बावड़ी और कुओं समेत कई स्त्रोतों में पानी उपलब्ध तो हो जाता है, लेकिन वह इतना खारा होता है कि उसे कोई आम इंसान पी नहीं सकता है. लेकिन हम गांव वाले वही खारा पानी पीने को मजबूर हैं. इसकी वजह से लोग अक्सर बीमार ही रहते हैं. ऐसे में बच्चों की सेहत पर क्या असर रहता होगा, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है. वह कहती हैं कि इस पानी के इस्तेमाल की वजह से बच्चों में अक्सर उल्टी और दस्त की शिकायत रहती है. वहीं गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को भी मजबूरीवश इसी खारे पानी का इस्तेमाल करनी पड़ती है, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है. लेकिन इस पानी के इस्तेमाल के अतिरिक्त हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं है. वह बताती हैं कि बच्चे और बुजुर्ग मिलकर उनके परिवार में सात सदस्य हैं और सभी इस खारे पानी की वजह से अक्सर बीमार ही रहते हैं.

वहीं शारदा देवी की पड़ोसी 40 वर्षीय सुमन बताती हैं कि केवल इंसान ही नहीं, बल्कि पालतू मवेशी भी इस खारे पानी को पीने के लिए मजबूर हैं. जिसकी वजह से अक्सर उनकी मौत हो जाती है. वह बताती हैं कि उनके पास 12 भैंस और 8 बकरियां थी. जिसे उन्होंने मवेशी पालन के तहत बैंक से क़र्ज़ लेकर ख़रीदा था ताकि उनका दूध बेचकर आमदनी का माध्यम बनाया जाए. लेकिन खारा पानी पीने के कारण अब तक उनकी सात भैंस और तीन बकरियां मर चुकी हैं. वहीं बाकी बचे मवेशी भी यह पानी पीकर अक्सर बीमार रहने लगे हैं. मैंने जिस उद्देश्य से इन मवेशियों को ख़रीदा था, वह पूरा होता नज़र नहीं आ रहा है. अब मुझे यह चिंता सता रही है कि मैं अब बैंक का क़र्ज़ कैसे चुकाऊंगी? सुमन बताती हैं कि अब मैं इन पशुओं के लिए प्रतिदिन खेतों से पानी लाती हूं, जो सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है. हालांकि वह भी खारा होता है लेकिन इसके अपेक्षाकृत कम होता है. सुमन के पति फौजी सिंह बताते हैं कि अक्सर गांव वाले मिलकर लूणकरणसर से पानी का टैंकर मंगाते हैं. एक टैंकर की कीमत एक हज़ार से डेढ़ हज़ार के बीच होती है. हम ग्रामीण प्रतिदिन टैंकर मंगवाने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए सप्ताह में एक दिन आपस में चंदा इकठ्ठा कर टैंकर मंगवाते हैं. लेकिन जब पानी ख़त्म हो जाता है तो फिर वही खारा पानी का उपयोग करनी पड़ती है.

करणीसर गांव के सरपंच हेतराम गोदारा बताते हैं कि इस गांव के अधिकतर परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करता है. कुछ परिवार के पास खेती के लायक जमीन है, जिससे इतना ही अनाज उगता है जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें. अधिकतर परिवार के लोग दैनिक मजदूरी करते हैं. ऐसे में उनके द्वारा प्रतिदिन पानी का टैंकर मंगवाना संभव नहीं है. इसलिए ज्यादातर परिवार कुओं और बावड़ियों में उपलब्ध खारा पानी का ही इस्तेमाल करते हैं और अपने पशुओं को भी यही पिलाने के लिए मजबूर हैं. वह बताते हैं कि अभी तक करणीसर गांव में प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल जल योजना नहीं पहुंची है. जिसकी वजह से ग्रामीणों को फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है.

हेतराम के अनुसार वह इस संबंध में लगातार उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा रहे हैं. उन्होंने कई बार ब्लॉक मुख्यालय में इस संबंध में पत्र लिखकर गांव में जल जीवन मिशन के तहत पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने का अनुरोध कर चुके हैं. वह बताते हैं कि लूणकरणसर ब्लॉक के कई गांवों में भूमिगत जल फ्लोराइड युक्त है. जिसका प्रभाव गांव वालों और उनके मवेशियों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है. ज्ञात हो कि फ्लोराइड युक्त पानी वैसे तो शरीर के लिए लाभदायक होता है, लेकिन जब यही तय सीमा से अधिक हो जाता है तो शरीर के लिए हानिकारक बन जाता है. करणीसर और उसके आसपास के गांवों के पानी में यही फ्लोराइड तय सीमा से बहुत अधिक पाया जा रहा है. ऐसे में इसके लगातार प्रयोग से लोगों को हड्डियों की बीमारियां हो जाती हैं. जिसमें हड्डी का टेढ़ापन और पूरे शरीर में दर्द की परेशानी रहती है. शुरू में इस पानी की वजह से उल्टी और दस्त आते हैं. लेकिन इसके लगातार इस्तेमाल से भविष्य में व्यक्ति के दिव्यांग होने का खतरा बढ़ जाता है.

हाल ही में राजस्थान सरकार ने पेयजल योजना सुदृढ़ीकरण एवं पुनरुद्धार योजना के अंतर्गत करणीसर समेत लूणकरणसर ब्लॉक के कई गांवों में पेयजल समस्या को दूर करने की एक योजना को स्वीकृति दी है. जलप्रदाय योजना के तहत इन गांवों के जलापूर्ति को इंदिरा नहर से जोड़ा जाएगा. जिससे ग्रामीणों और उनके मवेशियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा. इस योजना पर राज्य सरकार ने 16 करोड़ 50 लाख रूपए खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की है. आशा की जानी चाहिए कि यह परियोजना जल्द पूरा हो जाए ताकि करणीसर और उसके आसपास के ग्रामीणों और उनके मवेशियों को पीने का साफ़ पानी उपलब्ध हो सकेगा.

(चरखा फीचर)

धुआंधार कावड़ यात्रा 26 जुलाई को

महेश्वर से मां नर्मदा का पावन जल भर निकलेंगे कावड़ यात्री, 29 को धारनाथ का करेंगे जलाभिषेक

धार। 21 वर्षो से निकल रही प्रसिद्ध धुआंधार कावड़ यात्रा 26 जुलाई को महेश्वर से मां नर्मदा का पावन जल भर निकलेगी, कावड़ यात्री 29 जुलाई को मां नर्मदा के पावन जल से धारनाथ का जलाभिषेककरेंगे ।

25 जुलाई गुरुवार को महेश्वर में धुआंधार कावड़ यात्रा संकट मोचन हनुमान मंदिर मोनी बाबा के आश्रम पर विश्राम कर 26 जुलाई को मां नर्मदा का पावन जल भर कर धुआंधार कावड़ यात्रा निकाली जाएगी । 26 जुलाई शुक्रवार को जहांगीरपुरा में विश्राम होगा। 27 को जहांगीरपुर से देदला फाटा, वृंदावन गार्डन में विश्राम होगा ।28 जुलाई को वृंदावन गार्डन से कावड़ यात्रा शुरू हो कर धार आगमन होगा। पाटीदार चौराहे पर धार राजपूत समाज धर्मशाला में विश्राम होगा। 29 जुलाई सोमवार को धुआंधार कावड़ यात्रा का चल समारोह निकाला जायगा जो राजपूत धर्म शाला से प्रारंभ होकर घोड़ाचौपाटी,मोहन टाकीज, धानमण्डी, शनिगली, होकर धारेश्वर मंदिर में जलाभिषेक किया जायगा। जुलूस धारेश्वर मंदिर से फिर से शुरू होकर शनि गली,आनंद चौपाटी, राजवाड़ा, पौ चौपाटी ,होते हुए धुआंधार मंदिर पर जुलूस का समापन होगा। यात्रा संयोजक सूर्य दुबे ने बताया कि आयोजक धुआंधार कावड़ यात्रा समिति ने यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली है। वरिष्ठ समाजसेवी - हमारे मार्गदर्शक समंदर सिंह पटेल (उटावद), शैलेष यादव (कामरेड), राजू गुरु ,धर्मेंद्र जोशी , सुनील अग्रवाल , शिवा कैप्टन , दादू गुरु , पप्पू प्रजापत , महेश बाबा (धुआं धार), मनोज बाबा , मनोज सुहेल , राम किशन पाटीदार, हीरा सेठ बगड़िया, अंबाराम जी हटीला बोस , अर्जुन रघुवंशी देदला, संदीप रघवंशी राजा के मार्गदर्शन में कावड़ यात्रा निकलेगी।

कांग्रेस ने मनाई चंद्रशेखर आजाद की जयंती चंद्रशेखर आजाद के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी होगी

देवास / मोहन वर्मा। चंद्रशेखर आजाद स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा नाम रहा है जिसने अपनी उपस्थिति से स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को एक नई दिशा दी वही देश के युवाओं को देश की आजादी में प्राण-प्रण से भाग लेने की प्रेरणा दी। बाल अवस्था से ही चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजी हुकूमत के देश के लोगों पर जो जुल्म देखें उससे उनके मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा थी ।उन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग लेकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हुए पुरजोर विरोध किया। युवा क्रांतिकारियों के साथ अंग्रेजी हुकूमत के छक्के छुड़ा दिए।

स्वतंत्रता के आंदोलन में अपनी शहादत दी जिसका परिणाम रहा कि हमें आजादी मिली। उक्त विचार शहर जिला कांग्रेस द्वारा एमजी हॉस्पिटल के तिराहे पर लगी चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ,भगवान सिंह चावड़ा, रेखा वर्मा चंद्रपाल सिंह सोलंकी ने संबोधित करते हुए कहे। इसी के साथ श्री राजानी ने कहा कि आज के दिन हम संकल्प लें कि हम महान शहीद चंद्रशेखर आजाद के बताए हुए मार्ग पर चलकर देश को एक रख ने की दिशा में काम करते रहेंगे। कार्यक्रम का संचालन कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर शर्मा ने किया एवं आभार प्रहलाद गुरु जी ने माना । इस अवसर पर कांग्रेस नेता नजर शेख डॉ मंसूर शेख संजय कहार अनिल शर्मा इरफान कुरैशी छोटू सिंह गुर्जर संजय रैकवार संतोष सिंह बेस कल्लू भाई राष्ट्रीय शुभम सोलंकी महेंद्र सिंह ठाकुर अनिल शर्मा नवीन सोलंकी जयप्रकाश मालवीय,जितेंद्र मालवीय ओम राठौड़ कुद्दूस शेख,सुनील सोलंकी गोलू विजयवर्गीय बाबूलाल भाट सहित कांग्रेस जन उपस्थित थे।

देवास ने बचाया 200 करोड़ लीटर पानी ,आगे बचाएगा 1000 करोड़ लीटर : कलेक्टर गुप्ता

देवास। देवास शहर ने इस बार अमृत संचय अभियान के तहत 200 करोड़ लीटर पानी बचाया है और शहरवासियों के सम्मिलित प्रयासों से ये उम्मीद की जा सकती है कि बरसात में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग और सोक पिट के माध्यम से आने वाले समय में हम सब मिलकर 1000 करोड़ लीटर पानी भी बचा सकते हैं ।ये बात जिला कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता ने आज सेन थाम एकेडमी में जल संचय को लेकर आयोजित कार्यशाला में कही ।

श्री गुप्ता ने उपस्थित बच्चों और पालकों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे संवेदनशील होते है और भविष्य में पानी की कमी को देखते हुए उनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि इस गंभीर मुद्दे पर वे और परिजन मिलकर पानी संचय भी करेंगे और बचायेंगे भी। आपने कहा कि बेहतर पर्यावरण के लिए पेड़ लगाना जरूरी है मगर पेड़ के लिए और जीवन के लिए पानी हम सबकी प्राथमिकता है।

आपने दिल्ली,बैंगलुरू के उदाहरण देते हुए कहा कि दिल्ली गैस चेंबर में बदलता जा रहा है और बैंगलुरू में जहां पिछले साल अतिवृष्टि के हालात थे वहीं इस बार पानी की कमी है। हम खुद ये हालात पैदा कर रहे है। तालाबों की जगहों पर बहुमंजिला इमारतें, सीमेंट कांक्रीट के रोड,पैवर्स लगाकर जमीन में पानी जाने से रोक रहे है। कलेक्टर श्री गुप्ता ने सभी से कहा कि रूफ वाटर हार्वेस्टिंग और सोक पिट के माध्यम से जलसंचय करते हुए हम खुद को,बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को पानी की कमी से बचा सकते है।

कार्यक्रम के आरंभ में एकेडमी की श्रीमती हैंसी थॉमस और सुनील थॉमस ने अतिथियों का स्वागत किया। अमृत संचय टीम के श्रीकांत उपाध्याय ने इस अभियान के बारे में बताया। इस अवसर पर बच्चों और परिजनों ने जिलाधीश से सार्थक संवाद करते हुए सवाल भी पूछे । अभियान के डॉ सुनील चतुर्वेदी ने उपस्थित लोगों की जिज्ञासाओं और प्रश्नों के जवाब दिए।

एकेडमी के सुनील थॉमस ने जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह स्कूल ने अपनी छत के माध्यम से 25 लाख लीटर तथा ग्राउंड के माध्यम से 2 करोड़ लीटर पानी बचाकर अभियान में अपना योगदान दिया है। स्कूल के छात्रों ने पर्यावरण में सहयोग करते हुए पचास हजार सीड बॉल भी बनाए है जिनमे से तीस हजार शंकरगढ़ और बीस हजार पालकों और बच्चों के माध्यम से शहर में वृक्षारोपण के लिए उपयोग किए जायेंगें

कार्यक्रम में टीम अमृत संचय के मोहन वर्मा, अरविंद त्रिवेदी,हिमांशु भावसार,महेश सोनी तथा प्रतापसिंह ठाकुर भी उपस्थित थे।

महालक्ष्मी वेयरहाउस की कार्यप्रणाली से परेशान किसानों ने किया जाम, चार दिनों से खड़े थे मूंग से भरे ट्रेक्टर

हीरालाल गोलानी सोहागपुर

इस साल प्रशासन ने सोहागपुर के मध्य किसी भी वेयरहाउसो में मूंग की खरीदी के केंद्र नहीं बनाए गए हैं। इससे क्षेत्र के किसान खासे परेशान हैं। प्रशासन की कलाकारी तो देखिए कि सेमरी हरचंद से लगे महालक्ष्मी वेयरहाउस गुरमखेड़ी बिलेक लिस्टेड है। लेकिन उसी परिवार जनों ने सत्ता से जुड़े महालक्ष्मी वेयरहाउस गुरमखेड़ी को मूंग खरीदी का केंद्र बना दिया गया। हाल ही में चार,चार, पांच पांच दिनों से मूंग से भरे खड़े ट्रेक्टर महालक्ष्मी वेयरहाउस सेमरी हरचंद में तुलाई की शिथिलता के कारण किसानों की सब्र का बांध टूट गया। इससे किसानों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। इसी बीच नर्मदापुरम जा रहे पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं सोहागपुर विधानसभा चुनाव 2023के प्रत्याशी पुष्पराजसिंह पटैल को किसानों ने रोक लिया। तथा समस्या बताने लगे कि गरीब किसानों की मूंग तुलाई नहीं हो पा रही है। वहीं तुलाई का नम्बर ही नहीं लग पा रहा है। जाम की खबर लगते ही अनुविभागीय अधिकारी बृजेंद्र रावत, एसडीओ पुलिस संजू चौहान, कृषि विस्तार अधिकारी राम अवतार सिंह आदि पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। काफी देर

समझाईस के बाद चक्का जाम खुलवाया गया। वहीं तुलाई करने का आश्वासन दिया गया।

कृषि विस्तार अधिकारी- कृषि विस्तार अधिकारी राम अवतार सिंह ने बताया कि महालक्ष्मी वेयरहाउस में नाफेड का टारगेट पूरा हो गया है।इसी कारण तुलाई नहीं हो रही थी।अब प्रशासन ने कोटा बढ़ा दिया है। तुलाई फिर से प्रारंभ हो गई है। इसके अलावा अनुविभागीय अधिकारी एवं हमारे द्वारा किसानों की समस्याओं, क्षेत्र में मूंग की उपलब्धता एवं खरीदी केन्द्रों की कमी से कलेक्टर मेडम को अवगत करा दिया गया है।

पूर्व जिला कांग्रेस के बोल- पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं सोहागपुर विधानसभा चुनाव 2023 के प्रत्याशी पुष्पराज सिंह पटैल ने बताया कि चुनाव में इस क्षेत्र से विधायक विजयपालसिंह काफी मतों से पिछड़ गए थे।इसी कारण विद्वेषपूर्ण कार्यवाही क्षेत्र के नागरिकों से की जा रही है। बाबई से लेकर तवा तक मूंग की खेती नहीं के बराबर होती है। लेकिन सोहागपुर ब्लाक में करीबन 95 प्रतिशत किसान मूंग की फसल की बोवनी करते हैं।फिर भी विधायक के इशारे पर प्रशासन ने सोहागपुर क्षेत्र में खरीदी केन्द्रों को वंचित रखा है। वहीं केवल 2 सेमरी हरचंद,1 रेवामुहारी,1 गजनई, 2 शोभापुर एवं 2 रानी पिपरिया में केन्द्र बनाएं गए हैं।जो किसानों की मूंग की उपज के हिसाब से नाकाफी हैं। प्रशासन को किसानों की मूंग उत्पादन के अनुसार खरीदी केंद्र बनना था। वहीं आपने आरोप लगाया है सत्ता पक्ष के वेयरहाउसों जिनमें गेहूं पहले से रखा हुआ है ऐसे वेयरहाउसों को खरीदी केंद्र बनना केवल सत्ता से जुड़े लोगों को लाभ पहुंचाना ही है?

विगत दिनों महालक्ष्मी वेयरहाउस सेमरी हरचंद में मारपीट हुई थी।जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जाता है कि सत्ता से जुड़े होने के कारण वेयरहाउस पर प्रशासन ने मामला नजर अंदाज कर दिया था ?

उर्दू व्यंग्य

मुजतबा हुसैन

अनुवाद - अख़्तर अली

बारिश का महीना बादल करे शोर

लीजिये श्रीमान आख़िरकर बारिश हो ही गई । मैंने तो पहले ही कहा था उपर वाले पर भरोसा रखिये उसने सूखा किया है तो गीला भी वही करेगा । आप तनाव में थे न कि बारिश हो ही नहीं रही है तो आप बधाई स्वीकार कीजिये की बारिश होने लगी है। एक मिनट एक मिनट बारिश की घोषणा मैं क्यों कर रहा हूँ बारिश तो अपने आगमन की घोषणा स्वयं करने में सक्षम है । यही तो वह मौसम है जो गरज और चमक के साथ ऐसी शान से आता है कि लगता है जैसे राजा महाराजा की सवारी आ रही हो । अन्य देशों की बरसात के बारे में हम बूंद भर भी नही जानते लेकिन अपने देश की बरसात के बारे में हमारा ज्ञान पानी के धारे की तरह तेज़ है हम अच्छे से जानते हैं कि यह हिम्मती और दिलेर होती है । यह दुश्मन पर पीठ के पीछे से हमला नही करती बल्कि इसकी सेना बादल और बिजली हमले के पहले शोर मचा देती है ।

हमारे देश की बरसात हमारे देश के नेताओं की तरह बहुत चालाक और होशियार होती है वह उसी वक्त आती है जब आप घर से बाहर हों और आपके पास रैन कोट और छाता न हो इस तरह बारिश आदमी को भीगा कर अपने होने का सबूत देती है । इसके साथ ही हमारे देश की बरसात पढ़ी लिखी बरसात होती है वह अखबार में मौसम विभाग की सूचना पढ़ कर आती है । अब आप ही कहिये ऐसा चमकीला चरित्र और किसी मौसम का है? दूसरे मौसम तो घोटाले की तरह आहिस्ता से आते हैं

और जांच की तरह चुपके से चले जाते हैं ।

मौसम विभाग की चेतावनी से मैं तो इतना प्रभावित हूँ कि जब अखबार में पढता हूँ कि कड़ाके की ठंड पड़ेगी तभी मेरे को ठंड लगती है । मौसम तो वही होता है जो आने से पहले मिडिया में छा जाये ।

बरसात का मौसम बहुत उम्मीदों वाला मौसम होता है। बचपन में जब हम छोटे थे और रात में तेज़ बारिश होती थी तो हमारे दिल में बहुत सी उम्मीदें जाग जाती थी कि काश इस बारिश में स्कूल की बिल्डिंग बह जाये लेकिन सुबह जब स्कूल पहुचते तो पता चलता स्कूल तो छोड़ो मास्टर साहब की छड़ी भी अपनी जगह पर सुरक्षित है । बारिश से सिर्फ हमारे ही नही धरती के सीने में भी उम्मीदें छिपी होती हैं जो बाद में सैकड़ों नन्हे मुन्ने पौधों की शक्ल में धरती के सीने से उबल पड़ती है ।

बरसात की एक खूबी यह होती है कि आदमी इससे बचने की हर संभव कोशिश करता है लेकिन हार जाता है बरसात उसे भीगा कर ही दम लेती है । आदमी सड़क पर रेनकोट और छतरी में भीग जाता है वह तो ठीक है लेकिन आप मेरी हालत देख लेंगे तो आपकी आँख बादल के तरह बरसने लगेगी क्योंकि मैं तो अपने कमरे के अंदर भी छाता लेकर बैठता हूँ तो भीग जाता हूँ । मैंने अपने मालिक मकान से कहा भी कि छत की मरम्मत तो करवा दीजिये तो वह कहता है दोष मेरी छत में नही आपके छाते में है । मकान की छत नही छाते की छत खराब है ।

बारिश के दिनों में सड़क पर रंग बिरंगी छतरियों का प्रदर्शन देखने को मिलता है । इसे ध्यान से देखेगे तो पता चलेगा इसमें आदमियों की छतरी अलग और औरतों की छतरी अलग अलग रंग और आकार की होती है । जब इस समय आदमी और औरतों के कपड़ों में फ़र्क खत्म होता जा रहा है तब शुक्र हैं कि इनकी छतरियों में तो कुछ फ़र्क बाकी है । आदमियों की छतरी बड़ी और औरतों की छतरी छोटी होती है और इतनी छोटी होती है कि इससे सिर्फ उनके चेहरे का मेकअप धुलने से बच जाता है और इनके लिये यही बहुत बड़ी बात है ।

बरसात के दिनों की एक ख़ासियत और होती है कि इन दिनों सड़क पर कीचड़ की कमी नही होती है । समान वितरण प्रणाली के जैसे हर सड़क और गली में पर्याप्त मात्रा में कीचड़ उपलब्ध रहता है । फिर भी सड़क पर उतना कीचड़ नही होता जितना कीचड़ दिमाग में और विभाग में होता है । यहाँ हर हाथ कीचड़ से सने है फ़िर भी बारिश से उत्पन्न हुए कीचड़ में फिसलने का एक अलग ही आनंद है । हर आदमी कीचड़ में फिसलने की इच्छा रखता है क्योकि कीचड़ में ख़राब होने के बाद ही लोग उसके कपड़ों की कीमत का अंदाज़ा लगाते हैं । अगर दुर्भाग्य से कोई कीचड़ में फिसलने का सौभाग्य प्राप्त न कर सके तो उसे निराश होने की ज़रूरत नही है क्योंकि साफ़ सुथरे कपड़ो पर कीचड़ उछालने के लिये यहाँ बरसो पहले कार का अविष्कार कर लिया गया है । हम ख़ाक नशीनो के लिये मोटर नशीनो का होना किसी उपलब्धि से कम नही है ।

अगर बरसात का लुत्फ़ लेना है तो पहले चाय और पकोड़े खाइये फ़िर बारिश के जमा हो गए पानी में कागज़ की कश्ती चलाइये और गुनगुनाइये जगजीत सिंह की ग़ज़ल 'ये कागज़ की कश्ती ये बारिश का पानी' ।

राइट क्लिक

राहत की दरकार से ज्यादा सरकार को टिकाए रखने वाला बजट

अजय बोकिल

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा सातवीं बार पेश देश के वर्ष 2024-25 के बजट में लोकसभा चुनाव के दौरान चर्चा में रही मोदी गारंटी की छाया ज्यादा नहीं दिखाई दी। बेशक यह बजट देश की आर्थिकी के विकास को आगे बढ़ाने वाला दूरगामी बजट है, लेकिन आम लोगों को बजट से तत्काल बड़ी राहत की जो उम्मीदें थीं, वह नदारद हैं। पहली नजर में यह साफ है कि मोदी सरकार की प्राथमिकता अपनी गठबंधन सरकार को बचाए रखने की है। जिस तरह जद यू और टीडीपी की बैसाखियों पर यह एनडीए सरकार चल रही है, उसके चलते बिहार और आंध्र प्रदेश पर मेहरबानी होना स्वाभाविक ही था। हालांकि मोदी सरकार ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू द्वारा उनके राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग ठुकरा दी है, लेकिन वो समर्थन के बदले केन्द्र से ज्यादा हिस्सेदारी मांगते और लेते रहेंगे, यह तय है। हैरानी की बात यह है कि इस साल जिन चार राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं, उन्हें भी बजट में कुछ खास नहीं दिया गया है। लेकिन दीर्घकालीन विकास की दृष्टि से देखें तो यह बजट विकास की बुनियाद को मजबूत करने तथा उसी दिशा में आगे बढ़ने के संकल्प से प्रेरित है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जहां इसे दूरगामी और देश को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला बजट बताया है वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे 'कुर्सी बचाओ बजट' की संज्ञा दी है। इस बजट से यह राजनीतिक संदेश भी स्पष्ट है कि मोदी सरकार को अपनी मजबूती पर पूरा भरोसा है। साथ ही उसे इस साल होने वाले चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए किसी लोकलुभावन टोटके की गरज नहीं है। अब यह मोदी सरकार का आत्मविश्वास है अथवा अति आत्मविश्वास, यह तो विस चुनाव नतीजों से पता चल जाएगा।

पूरे बजट को अगर राजनीतिक नजरिए से देखें तो मोदी सरकार 3.0 के बजट में वित्त मंत्री ने लोकसभा चुनाव का नरेटिव बदलने वाले मुख्यब मुद्दे जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई व किसानों की समस्या आदि को एड्रेस तो किया है, लेकिन आराम के साथ और वो भी कुछ घुमा फिरा कर। बेरोजगारी की बात करें तो वित्त मंत्री एक भी ऐसी घोषणा नहीं की, जिससे यह संदेश जाए कि खुद सरकार बड़े नियोक्ता के रूप में सामने आना चाहती है। इस मामले में ज्यादातर भरोसा निजी क्षेत्र और स्वरोजगार पर जताया गया है। सरकार बड़ी 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को पांच हजार रुपये का मासिक भत्ता देगी। लेकिन कितनी कंपनियां अनिवार्य रूप से इंटर्न रखेंगी और कितने इंटर्न रखेंगी, इसका कोई रोड मैप वित्त मंत्री ने नहीं दिया है। कांग्रेस नेता पी. चिदम्बरम ने इस पर यह कहकर चुटकी ली कि इंटर्नशिप भत्ते का प्रावधान कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़कर किया गया लगता है। दूसरी तरफ सरकार का जोर रोजगार कौशल विकास और अन्य रोजगार के अवसर बढ़ाने पर है। जबकि युवाओं को उम्मीद थी कि सरकार बड़े पैमाने पर सीधी भर्तियों का ऐलान करेगी। लेकिन वैसा कुछ बजट में नहीं है। अलबत्ता बजट में देश के 4.1 करोड़ युवाओं के लिए पांच साल में रोजगार-कौशल और अन्यल अवसरों के लिए प्रधानमंत्री की पांच योजनाएं और पहले की गई हैं, जिनमें : ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15 हजार रुपये तक के एक महीने का वेतन तीन किस्तों में देना, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को सीधे विनिर्दिष्ट स्केल पर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराना जो नौकरी के पहले चार साल में दोनों के ईपीएफओ योगदान पर निर्भर है, सरकार नियोक्ता को उसके ईपीएफओ योगदान के लिए दो साल तक हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 3000 हजार रुपये प्रत्येक महीना भुगतान का प्रावधान है। साथ ही अगले पांच साल की अवधि में 20 लाख युवाओं का कौशल बढ़ाने की बात कही गई है। सीधे नौकरी देना और नौकरी पाने के हालात पैदा करना दोनो अलग-अलग बातें हैं। इसी तरह महंगाई को लेकर भी सरकार खास चिंता में नहीं दिखी। उसने जनता को सीधे मिलने वाली किसी राहत का ऐलान नहीं किया।

जहां तक किसानों की बात है तो बजट में कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये की घोषणा हुई है। लेकिन किसानों की एमएसपी को कानूनी आधार देने की मांग का कोई जिक्र नहीं है। यहां तक कि किसान सम्मान निधि भी नहीं बढ़ाई गई है।

मोदी सरकार का एक बड़ा समर्थक देश का मध्यम वर्ग रहा है। लेकिन बजट में आयकर छूट व स्टैंडर्ड डिडक्शन वृद्धि के रूप में ऊंट के मुंह में जीरे जैसी राहत दी गई है। क्योंकि जो टैक्स स्लैब बनाए गए हैं, वो इतने छोटे हैं कि एक वेतन वृद्धि और डीए में ही स्लैब बदल सकता है। न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है। साथ ही न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। वित्त मंत्री का दावा है कि इससे 10 लाख रुपये से ज्यादा वेतन पाने वालों को सालाना 17,500 रुपये तक की बचत होगी। लेकिन पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

देश में अधोसंरचना विकास और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात है। पूर्वोदय नाम से पूर्व व पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास के लिए योजना है। समूचे बजट में सबसे ज्यादा मेहरबानी बिहार और आंध्र पर ही दिखती है। यहां तक कि भाजपा शासित यूपी, मप्र, राजस्थान, छग आदि बड़े राज्यों को भी ज्यादा कुछ नहीं मिला है। ऐसे में विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य जैसे कि पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, केरल आदि को तो उम्मीद भी रखनी नहीं चाहिए थी। विपक्षी दल इसे बजट में राजनीतिक भेदभाव के रूप में देख रहे हैं। इसी तरह देश में बढ़ती रेल दुर्घटनाओं के मद्देनजर रेल अधोसंरचना विकास के लिए ज्यादा रकम तथा सुरक्षा के बेहतर उपाय की बजट में नजर नहीं आए। किसी नई रेल का ऐलान भी नहीं हुआ। कैपिटल गेन टैक्स में राहत की बजाए उसे बढ़ाने के बजट प्रस्ताव से शेयर बाजार उठने की जगह और गिर गया।

कुल मिलाकर मोदी सरकार यह मान कर चल रही है कि दो नेताओं को साधने से पूरी सरकार पांच सालों के लिए सध जाएगी। इसमें यह अतिआत्मविश्वास भी छिपा है कि जनता उसे आजादी की शताब्दी मनने तक भाजपा ही सत्ता में बनाए रखेगी। आम जनता क्या चाहती है और क्या सोच रही है, इसकी सरकार को ज्यादा चिंता है, ऐसा नहीं लगता। लिहाजा यह बजट तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए नहीं बल्कि सुनहरे और विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक और कदम तथा किसी महापूजा के पहले किए जाने वाले रस्मी आचमन की तरह है। आशय यह कि स्वर्णिम भारत बनाना है तो कुछ परेशानियां तो झेलनी ही होंगी।

लेखक सुबह सवेरे के वरिष्ठ संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

सरपंचों ने मांगा 15 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन

23 हजार पंचायतों में कल से तालाबंदी ; सीएम हाउस घेरने पहुंचे भोपाल

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश के सरपंचों ने सरकार से 15 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन की मांग की है। इसके लिए 23 हजार पंचायतों से सरपंच मंगलवार को भोपाल पहुंचे। सबसे पहले वे लिंक रोड नंबर दो स्थित अंबेडकर पार्क में एकत्रित हुए। यहां सरपंचों के 3 गुटों ने सीएम हाउस घेराव का ऐलान कर दिया।

उन्हें मनाने पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे। लेकिन, सरपंच सहमत नहीं हुए, और उनके जाते ही वे सीएम हाउस की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वे आगे बढ़े पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। महिला सरपंच पुलिस के घेरे को तोड़कर आगे बढ़ने लगी तो बैरिकेड्स लगा दिए गए। बाद में पुलिस ने मुख्यमंत्री से मिलने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम देने का कहा। लेकिन, सरपंच हर जिले से एक प्रतिनिधि को बुलाने पर अड़े रहें। इस बीच सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह तोमर ने कहा- मुख्यमंत्री से मुलाकात की अफवाह फैलाई गई है। हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है। शाम करीब 5 बजे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी प्रदर्शन स्थल पहुंचे और सरपंचों की मांगों का समर्थन किया।

शाम को सरपंचों ने आपस में चर्चा की। बताया- कलेक्टर ने कहा कि मंत्री जी ने 15 दिन का समय मांगा है। हम गधे या कुत्ते के गले में ज्ञापन बांधकर अगले 15 दिन तक पंचायतों का काम ठप करेंगे।

आंदोलन खत्म करने का ऐलान...

सरपंच संघ के अध्यक्ष राजवीर सिंह तोमर ने 15 दिन का अल्टीमेटम देकर आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया है।

भोपाल के कोलार एसडीएम-तहसील ऑफिस पहुंचे कमिश्नर

अलमारी में रखी फाइल देखी, गांव में पटवारी से ई-केवायसी की प्रोसेस को समझा

भोपाल (नप्र)। भोपाल कमिश्नर डॉ. पवन कुमार शर्मा मंगलवार दोपहर में अचानक कोलार एसडीएम और तहसील ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने अलमारी में रखी फाइल देखी, जबकि सुहागपुर गांव में पहुंचकर पटवारी से ई-केवायसी की प्रोसेस को समझा।

राजस्व महाअभियान 2.0 के तहत कमिश्नर डॉ. शर्मा कोलार एसडीएम और तहसील ऑफिस पहुंचे थे। उनके साथ कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह भी थे। कमिश्नर ने राजस्व अभियान के तहत चल रहे राजस्व कार्यों की समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने पेंडिंग प्रकरण निपटाने पर जोर दिया। कहा कि अभियान में ज्यादा से ज्यादा प्रकरण निपटाए जाए।

राजस्व रिकॉर्ड भी देखा

कमिश्नर ने एसडीएम कोर्ट, तहसीलदार कोर्ट और पटवारी कक्ष का निरीक्षण किया। अलमारियों में रखें राजस्व रिकॉर्ड को भी देखा। यहां अपने कामों से पहुंचे लोगों से भी चर्चा की। इसके बाद कमिश्नर और कलेक्टर ग्राम सुहागपुर पहुंचे। यहां पटवारी के साथ कम्प्यूटर पर बैठकर ई-केवायसी की प्रोसेस को समझा। वहीं, किसानों से भी चर्चा की।

स्वावलंबन, भारतीय गांवों की है मुख्य शक्ति और विशेषता : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

गौ-माता की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी राशि

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि स्वावलंबन ही भारतीय गांव की मुख्य शक्ति और उनकी विशेषता रही है। हजारों साल की गुलामी के बावजूद भारतीय समाज ने अपने सांस्कृतिक स्वरूप और मूल्यों को गाँवों के स्वावलंबन के बल पर ही अक्षुण्य बनाए रखा है। आत्मनिर्भर पंचायत-समृद्ध मध्यप्रदेश विषय पर संगोष्ठी, पंचायतों और ग्रामों को आर्थिक रूप से अधिक सशक्त और विकास परक बनाने में प्रभावी रूप से सहायक होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आत्मनिर्भर पंचायत- समृद्ध मध्य प्रदेश विषय पर कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित संगोष्ठी के शुभारंभ अवसर पर यह बातें कही। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर संगोष्ठी का शुभारंभ किया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री ऐदल सिंह कंषाना, पशुपाल राज्य मंत्री श्री लखन पटेल एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह तथा अपर मुख्य सचिव श्री मलय श्रीवास्तव विशेष रूप से उपस्थित थे।

हर घर में जल और हर खेत में सिंचाई के लिए हो रहे हैं विशेष प्रयास- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्रावण मास में आरंभ हुई तीन दिवसीय कार्यशाला में महाकाल बाबा के जयघोष के साथ अपना संबोधन आरंभ करते हुए कहा कि भारतीय गाँव अनुशासित, संयमित और परम्परा व मूल्यों के अनुसार जीवन जीने के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वावलंबी ग्राम की व्यवस्था को सशक्त करने के प्रयासों से ग्रामीण जीवन अधिक सुविधाजनक हो रहा है और ग्रामीणों को प्रगति के भी पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा हर घर में नल से जल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन संचालित है तथा हर खेत में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था के उद्देश्य से स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार पूरे प्रदेश में प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में नर्मदा घाटी विकास के परिणाम सबके सामने हैं। केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश को 45-45 हजार करोड़ रूपए उपलब्ध कराए गए हैं। कालीसिंध-पार्वती और चंबल लिंक परियोजना की गतिविधियां आरंभ हो रही हैं। प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ने से किसानों का भी आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है।

दस से अधिक गाय पालने वालों को मिलेगा अनुदान- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार खेती के साथ-साथ पशुपालन को भी राज्य सरकार विशेष महत्व दे रही है। वृद्ध, अस्वस्थ, अपाहिज व असहाय गायों को पालने के लिए राज्य सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाएगी। कांजी हाऊसों को गौ-शाला के रूप में विकसित किया जाएगा और ऐसी गायों की व्यवस्था कांजी हाऊस में की जाएगी। गायों पर दिए जाने वाले अनुदान की राशि में भी वृद्धि की गई है, जो किसान 10 से अधिक गाय पालेंगे, उन्हें अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही फसलों के समान दूध पर बोनस उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी आरंभ की जाएगी। गौ-माता की संवदेनशीलता और आत्मीयता अद्भुत है, गौ-पालन को प्रोत्साहन देने के लिए भी राज्य शासन द्वारा विशेष नीति बनाई जा रही है।

पंचायतों के सम्मुख चुनौतियों और ई-पंचायत व्यवस्था पर भी होगी चर्चा

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि आत्मनिर्भर पंचायत-समृद्ध मध्यप्रदेश पर संगोष्ठी पंचायतराज व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सशक्त बनाने में मील का पत्थर सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि कृषि को लाभकारी बनाने, हरित मध्यप्रदेश, शहरीकरण से पंचायतों पर प्रभाव, केन्द्र पोषित योजनाओं का क्रियान्वयन, पेसा अधिनियम का क्रियान्वयन तथा वन क्षेत्र से लगी पंचायतों के सम्मुख चुनौतियों पर चर्चा के साथ ही ई-पंचायत व्यवस्था और पंचायतों की कार्य प्रणाली में वित्तीय अनुशासन तथा पारदर्शिता आदि विषयों पर चर्चा होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया प्रदर्शनी का अवलोकन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर आत्मनिर्भर पंचायत-समृद्ध मध्य प्रदेश विषय पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने द्रव्य जीवामृत, सामुदायिक जैव संसाधन केंद्र, मनरेगा से आजीविका, संवर्धन पोषण शिक्षा, सामुदायिक पोषण वाटिका और प्राकृतिक खेती पर मंडल मॉडल के स्टॉल देखे। जिला एवं जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सरपंचों के लिए आयोजित तीन दिवसीय संगोष्ठी में लगभग 500 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। आभार प्रदर्शन जर्मन कार्पोरेशन (जीआइजेड) के प्रोग्राम डायरेक्टर श्री फरहद वानिया ने किया।

संवेदनशील लेखन समाज का मार्गदर्शन करता है : उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

संयुक्त संचालक जनसंपर्क प्रलय श्रीवास्तव द्वारा लिखित 'अभिव्यक्ति के चार दशक' पुस्तक का किया विमोचन

भोपाल (नप्र)। उप-मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि सामाजिक समस्याओं पर संवेदनशील लेखन समाज का मार्गदर्शन करता है। कुरीतियों के सुधार के लिए प्रेरित करता है। हमेशा से लेखक और विचारकों ने शासन व्यवस्था को जागरूक किया है, सहयोग प्रदान किया है ताकि सुशासन की स्थापना हो और जन-सामान्य की समृद्धि और खुशहाली सुनिश्चित हो। उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने राज्य पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान भोपाल के सभागार में संयुक्त संचालक जनसंपर्क श्री प्रलय श्रीवास्तव द्वारा लिखित पुस्तक अभिव्यक्ति के चार दशक का विमोचन किया। उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने श्री श्रीवास्तव द्वारा उनके अनुभवों को रेखांकित करने के प्रयास की सराहना की। उन्होंने वेबसाइट और यूट्यूब चैनल जागरूक के लोगो का भी विमोचन किया।

कार्यक्रम में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पशुपालन एवं डेयरी विभाग श्री लखन पटेल, पूर्व मंत्री एवं विधायक श्रीमती अर्चना चिटनीस, विधायक श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी, पूर्व सांसद श्री आलोक संजर, वरिष्ठ पत्रकार श्री महेश श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री मनोज श्रीवास्तव सहित जनसंपर्क विभाग के वरिष्ठ और सेवानिवृत्त अधिकारी, पत्रकारगण और साहित्यकार उपस्थित थे।

पूर्व मंत्री एवं विधायक श्रीमती चिटनीस ने कहा कि शासकीय ज़िम्मेदारियों के निर्वहन की व्यस्तताओं के साथ अपने मौलिक विचारों को जीवंत रखना और समाज के हित में अनुभव साझा करने का यह प्रयास सराहनीय है। सेवानिवृत्त आईएएस श्री श्रीवास्तव ने कहा जनसंपर्क में प्रचार लेखन कार्य के साथ विचार लेखन का प्रयास सराहनीय है। वरिष्ठ पत्रकार श्री महेश श्रीवास्तव ने महाकवि कालिदास की कृति मेघदूत का उल्लेख करते हुए संयुक्त संचालक श्री श्रीवास्तव की कृति को मेघवर्णन की उपमा दी। उन्होंने कहा कि श्री प्रलय श्रीवास्तव ने अपने पिता मध्यप्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय श्री सत्यनारायण श्रीवास्तव की लेखनी को जीवंत रखा है।

संयुक्त संचालक जनसंपर्क श्री प्रलय श्रीवास्तव ने पुस्तक की विषय वस्तु का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि अभिव्यक्ति के चार दशक उनकी दूसरी पुस्तक है, जिसमें विगत 40 वर्षों के दौरान उनके द्वारा विभिन्न विषयों में लिखे गए समाचार पत्र- पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए लेखों का संग्रह तथा अन्य महत्वपूर्ण संस्मरण और संदर्भ समाहित हैं। उन्होंने सभी अतिथियों को अपनी पहली पुस्तक मध्यप्रदेश में चुनाव और नवाचार की प्रतियाँ भेंट की।

पुलिस पर पत्थर-शराब की बोतलें फेंकी, एसडीओपी घायल

गुना में महिला को पीटने वालों की दुकानें तोड़कर लौट रही टीम पर हमला

गुना (नप्र)। गुना में भीड़ ने पुलिस टीम पर पत्थर और शराब की बोतलें फेंकी। जेसीबी में तोड़फोड़ की। पत्थर लगने से एसडीओपी विवेक अष्ठाना घायल हो गए। पुलिस को आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को तितर-बितर करना पड़ा।

मामला फतेहगढ़ के विष्णुपुरा गांव का है। पुलिस और प्रशासन की टीम महिला से मारपीट के आरोपियों की दो दुकानें तोड़कर लौट रही थी। भीड़ की मांग थी कि आरोपियों के घर को भी तोड़ा जाए। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने दोपहर में फतेहगढ़ थाने का घेराव कर आरोपियों के मकान गिराने की मांग रखी थी।

दरअसल, फतेहगढ़ के विष्णुपुरा गांव में सोमवार सुबह जमीन के झगड़े में दो पक्ष आमने-सामने आ गए थे। एक पक्ष के आरोपी ने दूसरे पक्ष की महिला को बाल पकड़कर जमीन पर पटका। इसके बाद वह महिला के पेट पर घुटने रखकर बैठ गया और चेहरे-पीठ पर घूंसे मारे थे। इसका वीडियो भी सामने आया था। महिला से मारपीट मामले में फतेहगढ़ थाना प्रभारी एसआई कृपाल सिंह परिहार को लाइन अटैच किया जा चुका है।हिंदू संगठन और गांववालों ने मंगलवार दोपहर को फतेहगढ़ थाने का घेराव किया।

जिस जमीन के लिए झगड़ा, वो सरकारी- आरोपी फरीद खान के घर के पास सरकारी जमीन है। उसने पत्थर रखकर जमीन पर कब्जा जमा लिया है। वह यहां मवेशी बांधता है। गांव के ही रहने वाले दीपचंद लोधी का परिवार भी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। पहले भी दोनों परिवारों में इस बात पर झगड़े हो चुके हैं। सोमवार को दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए थे।

हिंदू संगठन और ग्रामीणों ने घेरा थाना- मंगलवार दोपहर 12.30 बजे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने फतेहगढ़ थाने का घेराव कर दिया। सभी मंडी में जुटे। यहां से रैली के रूप में थाने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि आरोपियों पर हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाई जाए। उनका घर बुलडोजर चलाकर ढहाया जाए। सरकारी जमीन से कब्जा हटवाया जाए।